

शिमला नगर निगम के वर्ष 2014-15 के संशोधित एवं वर्ष 2015-16 के बजट अनुमानों पर माननीय महापौर, नगर निगम शिमला द्वारा भाषण ।

सम्माननीय

मैं आप सभी का वर्ष 2015-2016 के बजट बारे हो रही इस 'विशेष बैठक' में स्वागत करता हूँ ।

सर्वप्रथम मैं माननीय पार्षदगणों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने नगर निगम के विभिन्न वार्डों में विकास कार्य करवाने हेतु व्यक्तिगत अहम भूमिका निभाई है तथा जनता की शिकायतों, समस्याओं को सुना व उन्हें सुलझाने में सहयोग प्रदान किया ।

नगर निगम शिमला का वित्त वर्ष 2015-16 का बजट ऐसे समय में प्रस्तुत किया जा रहा है जब पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है । देश व प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी इस संकट से अछूती नहीं है क्योंकि यहाँ भी विकास की दिशा उन्ही नव-उदारवाद की नीतियों पर आधारित है । इसके चलते समाज में आर्थिक असमानता पैदा हो रही है जिससे विशेषतः आम जन प्रभावित हो रहा है ।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि नगर निगम के विकासात्मक कार्यों व अन्य दायित्व का भार लोगों की आर्कोक्षाओं के अनुरूप दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है परन्तु उस अनपात में नगर निगम के आय के स्रोत नहीं बढ़ पा रहे हैं और न ही वर्तमान परिस्थितियों में शहर की जनता पर अनावश्यक करों का बोझ डाला जा सकता है । शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते हुये शहरीकरण तथा बढ़ती हुई मूलभूत सुविधाओं की माग को देखते हुये यह भी आवश्यक है कि निगम के चुने हुए जन-प्रतिनिधि होने के नाते हम सभी सदस्यगणों का उत्तरदायित्व है कि हम जनपक्ष में नगर निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से विचार-विमर्श करें और आय के स्रोत बढ़ाने पर कुछ ठोस निर्णायक फैसले लें ताकि नगर निगम की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके तथा शहर की जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सके ।

शहर के विकास कार्यों के लिए हमें शहर की जनता के सहयोग व सुझाव की आवश्यकता रहती है । इसलिए आर्थिक संकट से जूझते नगर निगम ने प्रथम बार, बजट बनाते समय शिमला शहरवासिया की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिमला की समस्त आवासीय कल्याण सोसायटी, ग्राम कल्याण सुधार सभाएं, स्वयं सेवी सस्थाएं, जिला स्तरीय शिमला शहरी सभी राजनितिक दलों व

व्यापार मण्डलों इत्यादि से निगम की आय की स्थिति में सुधार लाने बारे सुझाव/परामर्श लिये और उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 40 के अन्तर्गत गठित स्थायी समितियों की वर्ष 2014-15 में अभी तक 10 साधारण बैठकें, 7 साधारण कृत्यकारक समिति की बैठकें, 11 वित्त, संविदा और योजना समिति की बैठकें, 6 सामाजिक एवं न्याय समिति की बैठकें तथा 2 विशेष बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में शिमला शहर के विकास करने तथा शहरवासियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में अनेक प्रस्ताव/सुझाव पर विचार-विमर्श कर जनहित में निर्णय लिये गये।

1. वित्तीय स्थिति :

जैसा कि विदित है कि यह हमारी छठवीं निर्वाचित नगर निगम का तृतीय वार्षिक बजट प्रस्तुतीकरण है। नगर निगम की आय के स्रोत सीमित होने के कारण व सरकार से अपेक्षित सहायता प्राप्त न होने के कारण नगर निगम शहरवासियों को उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने व विकास करने में कठिनाई आ रही है। निगम की कम आय होने की स्थिति में आय व व्यय में भी असन्तुलन रहा है। इस चालू वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, 2014 तक निगम के आय स्रोतों से 2769.00 लाख रुपये और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 1787.54 लाख रुपये Development Grant सहित कुल राशि 4556.54 लाख रुपये की राजस्व आय और विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत अनुदान से राशि 1437.74 लाख रुपये की पूजीगत आय अर्थात् कुल आय राशि 5994.28 लाख रुपये की प्राप्ति हुई है। जबकि चालू वित्त वर्ष में 31 दिसम्बर, 2014 तक निगम का कुल व्यय राशि 5993.90 लाख रुपये हुआ है। निगम की आय व व्यय में बढ़ते अन्तर के बावजूद शहर का विकास करवाया जा रहा है।

शिमला एक ऐतिहासिक शहर है, प्रदेश की राजधानी है और पर्यटन की दृष्टि से यह शहर देश व विदेश में प्रख्यात है इसलिए इस शहर की गरिमा और गौरव बनाये रखना, स्वच्छ-सुन्दर, प्रदूषण मुक्त तथा विकासशील बनाये रखना हम सबका संयुक्त कर्तव्य बनता है।

नगर निगम के दायित्वों के निर्वहन हेतु सहायता व वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु पूर्व में जो प्रस्तावनाएं की गई थी उसमें मुख्यतः सरकार से अतिरिक्त अनुदान सहायता का अनुरोध किया गया था। जिसमें मुख्यतः 100 करोड़ रुपये

प्रतिवर्ष राजधानी विकास अनुदान(Capital Development Grant), चुंगी समाप्ति के बदले प्रतिभूति/डवैल्पमैण्ट ग्रांट को नगर निगम के कुल व्यय का 50 प्रतिशत करना, निगम सीमा में मिलाए गए नए क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष अनुदान राशि 600.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष, पानी की बल्क खरीद के बिलो की बकाया देय राशि के भुगतान हेतु विशेष अनुदान राशि, शहरी वनो तथा शहर के विभिन्न मार्गों के रख-रखाव, वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप निगम कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हेतु विशेष अनुदान राशि प्रदान करने हेतु आग्रह किया गया है। परन्तु इस बारे सरकार से कोई उचित सहयोग प्राप्त नहीं हुआ जिसके अभाव में शिमला शहर के विकास को सही दिशा व दशा प्रदान करने में कठिनाई आ रही है। शिमला शहर को एक बेहतर जीवन प्रदान करने वाले शहर के तौर पर विकसित करने हेतु नगर निगम सरकार से पुनः अनुरोध व आशा करता है कि सरकार इन अनुदानों को उपलब्ध करवाएगी।

74वें संवैधानिक संशोधन को लागू करने हेतु हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में वार्ड सभाओं के माध्यम से वार्ड कमेटियों के गठन का प्रावधान किया गया है। इससे शहर के विकास में जनता की सहभागिता सुनिश्चित होनी है। गत वित्त वर्ष के बजट में भी इस पर बल दिया गया था। परन्तु इसका कोई अधिक सकारात्मक परिणाम नहीं रहा। संवैधानिक उत्तरदायित्व के निर्वहन तथा विकास म जनता के सहयोग सुनिश्चित करने हेतु समस्त वार्डों में वार्ड कमेटियों का गठन शीघ्र किया जाएगा तथा वार्ड सभाओं के माध्यम से ही वार्ड के विकास की योजना बनाई जाएगी तथा इसके लिए प्रतिवार्ड 30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वार्ड कमेटियों के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक वार्ड से एकत्र होने वाले कुल राजस्व का न्यूनतम 10 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

चालू वित्त वर्ष में प्रत्येक पार्षद की अनुसंशा पर 10 लाख की धन राशि वार्डों में विकास कार्यों के लिए प्रदान की गई है। जिसे आगामी वित्त वर्ष में बढ़ाकर 15 लाख कर दिया जाएगा।

नगर निगम का मुख्य आय का स्रोत सम्पत्ति कर है। माननीय सदन ने सर्व सम्पत्ति से युनिट एरिया मैथड़ की कर प्रणाली में बदलाव व युक्तिकरण का प्रस्ताव पारित कर सरकार से हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधन करने हेतु भेजा था परन्तु सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तथा शहर में सम्पत्ति कर युनिट एरिया प्रणाली द्वारा एकत्र करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। वर्ष 2014-15 व वर्ष 2015-16 के लिए सम्पत्ति कर युनिट एरिया मैथड़ से एकत्रित करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। सम्पत्ति कर से इस वित्त वर्ष में 1809.71 लाख रुपये की आय अनुमानित है।

74वें संवैधानिक संशोधन के 12वें शैड्यूल क अन्तगत शहरी निकायों को प्रशासनिक व आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसमें शहरी वानिकी प्रबंधन भी शहरी निकायों का उत्तरदायित्व है। परन्तु प्रदेश सरकार द्वारा शिमला शहर व इसके साथ लगते वन क्षेत्राधिकार नगर निगम से अपने अधीन हस्तांतरित कर दिए हैं। अतः सरकार से पुनः आग्रह है कि पूर्व में अधिकृत शहरी वन क्षेत्र को नगर निगम शिमला को लौटाया जाए तथा इससे एकत्रित की गई आय नगर निगम शिमला को उपलब्ध करवाया जाए।

नगर निगम शिमला द्वारा ग्रीन फीस लगाने के दृष्टिगत राष्ट्रीय उच्च मार्ग विभाग को पुनः संशोधित प्लान भेजा जा रहा है, जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही राष्ट्रीय उच्च मार्ग के प्रवेश द्वारों का योजना अनुसार निर्माण किया जायेगा तथा आगामी वर्ष में ग्रीन फीस के लागू होने से नगर निगम को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।

2. कर्मचारी हितों के कार्य :

- नगर निगम शिमला द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए नगर निगम कर्मचारी कल्याण निधि के सृजन किये जाने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रयोजन हेतु उपयुक्त नियमों/उप विधियों को बनाया जाना प्रस्तावित है तथा कर्मचारियों के अशंदान व निजि उपक्रमों से स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त करके निधि का संचालन किया जाएगा। इस निधि से निगम कर्मचारी को आवश्यक कार्यों हेतु ऋण दिए जाने व कर्मचारियों के प्रतिभाशाली बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर वजीफा दिए जाने की सुविधा का प्रावधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी कर्मचारी के देहान्त पर उनके परिवार को तत्काल सुविधा प्रदान करने हेतु सहायता राशि फण्ड से दी जाएगी ताकि दुख की घड़ी में परिवार को फौरी सहायता मिल सके।
- वर्तमान में नगर निगम कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है और स्टाफ की कमी होने के बावजूद भी निगम प्रशासन का यथासम्भव प्रयास रहता है कि लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाये। इस चालू वर्ष में अहर्ता अवधि पूर्ण करने वाले 11 दैनिक वेतन भोगी व 3 अनुबन्ध कर्मचारी को नियमित किया गया। इसके अतिरिक्त निगम कर्मचारी के निधन उपरान्त उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर पदों को भरने की स्वीकृति सरकार द्वारा प्राप्त हुई है, जिसके तहत 7 आश्रितों को नियुक्ति दी गई है।

जिनमें से 5 आश्रितों ने निगम में कार्यग्रहण कर लिया है तथा दो आश्रितों ने लिपिक वर्ग के पद पर व परिवार के अन्य सदस्य को नियुक्ति देने हेतु आग्रह किया है तथा इनका मामला पुनः सरकार से स्वीकृति हेतु उठाया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगम शिमला द्वारा इस चालू वर्ष में निगम के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा देनी आरम्भ कर दी गई है।

- सब्जी मण्डी (सूजी लाईन) में विद्यमान निगम आवासों के साथ खाली पड़ी भूमि पर टाईप- II के तीन ब्लॉक में 24 आवास बनाना प्रस्तावित है। जिसके लिए राशि 2 करोड़ 26 लाख 63 हजार का प्राकलन बनाया गया है।
- वर्तमान में नगर निगम शिमला में विभिन्न श्रेणियों के बहुत से पद रिक्त पड़े हैं तथा स्टाफ की कमी होने के बावजूद भी निगम प्रशासन का यथासम्भव प्रयास रहता है कि लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाता रहे। इन रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए सरकार से स्वीकृति हेतु आग्रह किया गया है। स्वीकृति प्राप्त होते ही इन रिक्त पदों को शीघ्र भर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन श्रेणियों के पदों को निगम स्तर पर ही भरा जाना है उन्हें भरने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है।

माननीय सदस्यगण इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों एवं लक्ष्यों का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है :-

3. मार्ग एवं भवन विभाग :

- इस चालू वर्ष में शहर के विभिन्न वार्डों में सड़क पर तारकोल बिछाने के कार्य हेतु 1.35 करोड़ रु. व्यय किए गए हैं तथा कुछ सड़कों का कार्य करना शेष है जिसके लिए नगर निगम द्वारा निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं।
- इस चालू वर्ष में स्ट्रीट लाइटों के बिलों पर राशि 1 करोड़ 27 लाख, 91 हजार, 319 रुपये, मुरम्मत एवं रख-रखाव के लिए राशि 14,38,777/- रुपये तथा नये स्ट्रीट लगाने हेतु राशि 8,81,865/- खर्च किए गए हैं।
- आगामी वित्त वर्ष में लगभग रु. 1588.82 लाख की लागत से सड़कों, सम्पर्क मार्गों, रास्तों का निर्माण एवं रख-रखाव, स्ट्रीट लाइट मुरम्मत, नई स्ट्रीट लाइट फाईट्स इत्यादि प्रस्तावित है।

- दाड़नी के बगीचा में सौलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट प्रोजैक्ट के अधीन transfer station बनाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए 86.97 लाख का प्राकलन बनाया गया है तथा 64 लाख की लागत का अवार्ड पत्र ठेकेदार को दे दिया गया है।
- वर्ष 2015-16 में शिमला शहर में 7229 स्ट्रीट लाईटों को एल.ई.डी. में बदलने का प्रस्ताव है। जिन पर लगभग 5.10 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, लेकिन विद्युत बिल व रख-रखाव के खर्चों में भारी कमी आएगी।
- कसुम्पटी में रानी ग्राउण्ड में एक बहु-उद्देश्य आधुनिक पार्क का विकास करने के लिए हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग के आर्काटेक्ट विंग की सहायता से नगर निगम शिमला द्वारा राशि 1 करोड़ 29 लाख की लागत का प्राकलन बनवाया है। जिसमें play area के निर्माण, तीन gates, toilet block, harvesting tank, railings, park equipment plantations इत्यादि बनाये जाने प्रस्तावित है तथा जिसके लिए सतलुज जल विद्युत निगम लि0 से धन की उपलब्धता बारे पत्राचार द्वारा सम्पर्क किया गया है। इस पार्क के बनने से समाज के सभी लोग लाभान्वित होंगे तथा क्षेत्र का सौन्दर्य बढ़ेगा। इस पार्क का निर्माण शीघ्र आरम्भ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कनलोग में पार्क व पार्किंग का निर्माण करने की प्रस्तावना है।
- ऐतिहासिक रिज मैदान में प्रमुख रूप से भूस्खलन रोकने के आशय से एवं आय सृजन के उद्देश्य से लगभग रू. 20 करोड़ की अनुमानित लागत से पार्क, दुकानों, मल्टीपलैक्स, स्काईवाक, लिफ्ट, फूड कोट इत्यादि की सुविधा से सुसज्जित बहु-उद्देश्यीय परिसर की परिकल्पना अन्तिम चरण में है तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर का डिजाइन व मॉडल विकसित किया जा रहा है ताकि रिज मैदान का संरक्षण हो सके तथा जनाकर्षण का केन्द्र बिन्दु प्रस्तुत किया जा सके। प्रदेश सरकार की अनुमति प्राप्त होते ही इस परिसर का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
- नगर निगम द्वारा लोकल बस स्टैण्ड के नजदीक पुराने भवन का पुर्न निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है। इसके अतिरिक्त दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के निर्माणाधीन भवन में दो मंजिलों पर नगर निगम द्वारा व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।

- शिमला शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों व पर्यटकों की सुविधा के लिए आगामी वित्त वर्ष में 300 नये बेंच लगवाये जाने प्रस्तावित ह ।
- शिमला शहर में निगम की विभिन्न सड़कों जहाँ पर भी खाली स्थान उपलब्ध होगा उसका सौदर्यकरण शिमला की जनता की सहभागिता से करवाया जाना प्रस्तावित है तथा वहां पर उन्हें अपने कार्य के विज्ञापन का भी अधिकार होगा ।
- नगर निगम में रू. 2 करोड़ 80 लाख की लागत से सोलर सिटी मिशन के अन्तगत सोलर पावर प्लॉट का क्रियान्वयन किया जा रहा है । जिसके लिए स्थान का चयन किया जा रहा है ।
- शहर के विभिन्न वार्डों में 1000 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । साथ ही 1700 सोलर होम लाइट स्लम एरिया में लगाने के लिए भी अग्रसर है ।
- इस चालू वर्ष पंथाघाटी में तनजिन अस्पताल के पास एक हाई मास्ट लाइट और 3 हाई मास्ट लाइटें न्यु शिमला में बी.सी.एस. चौक, डी.ए.वी. स्कूल और बस स्टैण्ड में पर्यटन विभाग के सौजन्य से लगवाई गई ह ।

4. निगम परियोजनाएं :

- नगर निगम द्वारा तहबाजारियों के सशक्तिकरण एवं पुनर्वास के दृष्टिगत लिफ्ट के नजदीक बेकरी बिल्डिंग के स्थान पर पार्किंग तथा लिफ्ट सुविधा सहित 222 दुकानों का निर्माण कार्य राशि 3 करोड़ 85 लाख 53 हजार रूपये की लागत से किया जाना है । जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है तथा औपचारिताएं पूर्ण होने पर 31 मार्च से पूर्व निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा । इस परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा 2.50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है जिसकी पहली किश्त 1.25 करोड़ नगर निगम शिमला को प्राप्त हो चुकी है ।
- राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संजौली के समीप 2500 वर्ग मीटर क्षेत्र पर रू. 24 करोड़ 70 लाख की अनुमानित लागत से 400 वाहनों के लिए पी.पी.पी. आधार पर पार्किंग का निर्माण प्रगति पर ह । इसमें लगभग 40 हजार वर्ग फुट व्यवसायिक क्षेत्र प्रस्तावित है । 30 वर्षों की कन्सेशन

(Concesseion) अवधि में नगर निगम को प्रति वर्ष रू. 96 लाख की आमदनी होगी, जो प्रति 2 वर्षों में 10 प्रतिशत बढ़ेगी। प्रस्तावित नौ मंजिला परिसर वाले भवन मे से लगभग 250 वाहनों की पार्किंग क्षमता वाली चार मंजिलों को शीघ्र ही जनसाधारण के लिए खोल दिया जाएगा तथा पूरे प्रोजैक्ट का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

- छोटा शिमला में 1832 वर्ग मीटर क्षेत्र में रू. 11 करोड़ 68 लाख की अनुमानित लागत से 250 वाहनों के लिए पार्किंग का निर्माण पी.पी.पी. आधार पर प्रगति पर है। 30 वर्षों की कन्सैशन (Concession) अवधि में नगर निगम को रू. 36 लाख प्रतिवर्ष की आय होगी, जोकि प्रति दो वर्षों में 10 प्रतिशत बढ़ेगी। परिसर में लगभग 30 हजार वर्गफुट व्यवसायिक क्षेत्र प्रस्तावित है तथा इस पूरे प्रोजैक्ट का निर्माण कार्य जून, 2015 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
- लिफ्ट के समीप 6471.24 वर्गमीटर क्षेत्र रू. 46 करोड़ 11 लाख की अनुमानित लागत से 700 वाहनों के लिए पार्किंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 30 वर्षों की कन्सैशन (Concession) अवधि में नगर निगम को प्रतिवर्ष रू. 1 करोड़ की आय होगी जोकि प्रति 2 वर्षों में 10 प्रतिशत बढ़ेगी, परिसर में लगभग 40 हजार वर्गफुट व्यवसायिक क्षेत्र बनाया जाएगा तथा इस का निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2015-16 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
- विकासनगर में 1062 वर्ग मीटर क्षेत्र पर 174 वाहनों की पार्किंग क्षमता वाले परिसर का निर्माण कार्य सरकार से नक्शों की स्वीकृति प्राप्त होने पर शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जाएगा। 40 वर्षों की कन्सैशन (Concession) अवधि में नगर निगम शिमला को प्रतिवर्ष रू. 16 लाख आमदनी होगी, जो प्रति 3 वर्षों में 10 प्रतिशत बढ़ेगी।
- नगर निगम द्वारा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल, 2015 से संजौली से पुलिस चौकी लक्कड़ बाजार, सी.टी.ओ. से एडवांस स्टडी होते हुए बालूगंज, छोटा शिमला चौक से शिमला क्लब तक तथा नवबहार से रिचमाउण्ट रेन शैल्टर तक लोगों की सुविधा के लिए आने-जाने हेतु बैटरी चलित गोल्फ कार्ट चलाने की योजना है इन बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिका व मरीजों के लिए 60 प्रतिशत सीटें आरक्षित होगी। इन बैटरी चलित गोल्फ कार्ट का किराया नगर निगम द्वारा निर्धारित किया जाएगा व जिस हेतु औपचारिताएं शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी।

- नगर निगम द्वारा शिमला शहर के लोगों व सैलानियों के लिए पर्यटक सूचना केन्द्र बायपास रोड़ टूटीकण्डी से रिज वाया नगर निगम पार्किंग हाई कोर्ट, रोप-वे को पी.पी.पी. के आधार पर बनाने हेतू एच0पी0आई0डी0बी0 द्वारा निविदाएं बुला करके खोल दी गई हैं तथा उन पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। इस रोप-वे को बनाने के लिए जिन स्थानों का चयन किया गया है उनसे सम्बन्धित राजस्व कागजात एकत्रित किए जा रहे हैं तथा जहाँ-जहाँ पर वन भूमि आने की सम्भावना है, उसका एफ.सी.ए. के अन्तगत स्वीकृति हेतु मामला वन विभाग से उठाया जाएगा। आगामी वित्त वर्ष में इसका निर्माण कार्य शुरू करने की प्रस्तावना है तथा इस रोप-वे से शहर के विकास के लिए 11 करोड़ प्रतिवर्ष नगर निगम को आय प्राप्त होगी।
- शिमला शहर में यातायात की समस्या से निजात पाने के लिए दो अन्य रोप-वे तारादेवी से कुफरी वाया संकट मोचन, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, पुराना बस अड्डा, जाखू मन्दिर तक तथा तारादेवी रेलवे स्टेशन से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वाया कसुम्पटी, छोटा शिमला, टूटीकण्डी, पुराना बस अड्डा तक रोप-वे व दो टनलों का निर्माण लिफ्ट से लक्कड़ बाजार तथा लिफ्ट से हिमफैड पम्प नजदीक नवबहार तक बनाने की परियोजना है। इन परियोजनाओं के लिए वर्ल्ड बैंक से वित्तीय सहायता लेने हेतू परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया है। वर्ल्ड बैंक द्वारा इन परियोजनाओं को लेकर 19 फरवरी को विस्तृत रिपोर्ट सहित दिल्ली में आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण किया है। इन परियोजनाओं को अमल में लाने के लिए कन्सेप्ट नोट राज्य सरकार को भेज दिया है। जहाँ से यह केन्द्र सरकार के DEA व MoUD को भेजा जाना है। इन राप-वे व टनलों के निर्माण से शिमला शहरवासियों को जहाँ यातायात की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं शहर के पर्यावरण व विकास के साथ-साथ सैलानी भी लाभान्वित होंगे।
- नगर निगम शिमला द्वारा पार्किंग की समस्या को देखते हुए शहर के विभिन्न स्थानों में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कैथू में मारनिंग व्यु के पास, स्नो व्यु के पास, केपिटल होटल के नीचे पुलिस लाईन कैथू सड़क पर, बालूगंज चौक पर, प्राईमरी स्कूल, चक्कर नजदीक हवाघर, बालूगंज बाजार नजदीक पुलिस स्टेशन, हनुमान मन्दिर खलीनी, सेन्ट जवियर स्कूल, संजाली तथा ढली में सामुदायिक भवन के नजदीक पार्किंग का निर्माण करने के लिए स्थान चयनित किए गए। इन सभी चयनित पार्किंग स्थलों को पी.पी.पी. के आधार पर निर्माण करने की योजना है। जैसे ही इन चयनित स्थलों की भूमि सम्बन्धी औपचारिकताएं पूर्ण होगी। आगामी वित्त वर्ष 2015-16 में इनके पी.पी.पी. आधार पर निर्माण हेतू प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके

अतिरिक्त न्यु शिमला में सेक्टर-II बस स्टैण्ड के नजदीक पार्किंग का निर्माण करने की प्रस्तावना है ।

- शिमला शहर में पार्किंग समस्या से निजात पाने के लिए कार्ट रोड़ पर जहाँ-जहाँ पर सड़क की चौड़ाई ज्यादा है वहाँ पर येलो लाईन लगाकर के गाड़ियों पार्क करने का प्रावधान किया जाएगा । इससे सम्बन्धित मामला लोक निर्माण विभाग से उठाया गया है । लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र आने पर 850 गाड़ियों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी तथा साथ में नगर निगम की आय में भी बढ़ौतरी होगी ।
- शिमला शहर में पार्कों के निर्माण हेतु विभिन्न वार्डों में 40 स्थानों का चयन किया गया है । इनमे से जिन स्थानों पर भूमि की स्थिति स्पष्ट थी तथा जिसमें किसी तरह की वन भूमि सम्बन्धी राजस्व विवाद नहीं था उन चयनित स्थानों पर सतलुज जल विद्युत निगम लि० की वित्तीय सहायता से 5 पार्कों का निर्माण किया जा रहा है, उनमें से 3 पार्क का न्यु शिमला में, 1 का फलावरडेल में निर्माण किया जा चुका है तथा ढिंगुधार में कार्य प्रगति पर है । सतलुज जल विद्युत निगम लि० द्वारा शिमला में पार्कों के निर्माण हेतु रू. 3 करोड़ 35 लाख की सहमति दी गई थी, जिसमे से लगभग 26 लाख रू० की राशि नगर निगम को उपलब्ध करवा दी गई है । इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों में पार्क बनाने की सूची भी सतलुज जल विद्युत निगम लि० को उपलब्ध करवाई गई है । जिसके लिए उनसे पुनः वित्तीय सहायता हेतु आग्रह किया गया है ।
- स्थानीय लोगों व पर्यटकों के लिए विशेषतया महिलाओं एवं बच्चों के मनोरंजन के लिए रानी झाँसी पार्क में लगभग रू 4 करोड़ की लागत से कृत्रिम बर्फ स्केटिंग, स्पोर्ट्स, डांसिंग इत्यादि का टर्फ तैयार किया जाएगा ।
- सब्जी मण्डी मैदान में लगभग रू. 100 करोड़ की लागत से डी.बी.ओ.टी. आधार पर HPIDB के माध्यम से प्रस्तावित बहु-उद्देशीय परिसर की औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं आगामी वित्त वर्ष में इसका निर्माण कार्य आरम्भ करने का लक्ष्य है । कार्य पूर्ण होने पर नगर निगम को न्यूनतम रू. 2 करोड़ प्रतिवर्ष आय का अनुमान है ।
- नगर निगम द्वारा लोगों की निगम से सम्बन्धित शिकायतों व उनके शीघ्र निवारण करने के उद्देश्य से महापौर, उप-महापौर, सभी निगम पार्षदों, अधिकारियों, कनिष्ठ अभियन्ताओं व सफाई निरीक्षकों के साथ ग्रुप बनाकर

Whatsapp messenger के माध्यम से जोड़ दिया गया है ताकि लोगों की आंकाक्षाओं के अनुरूप उनकी शिकायतों का निपटारा किया जा सके व आम जनता को होने वाली दिक्कतों/असुविधाओं की जानकारी उपलब्ध हो सके। Whatsapp messenger का सीधा सम्बन्ध आयुक्त व सहायक आयुक्त से होगा जिससे उन्हें दिन-प्रति-दिन के क्रियाकलापों की जानकारी मिलती रहेगी तथा समय-समय पर जनहित में अधिकारियों/कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिये जा रहे ह और इस से समस्याओं के निवारण में काफी तीव्रता आई है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा स्थापित कन्ट्रोल रूम में टैल फ्री नम्बर 1916 पर 24 घण्टे शिकायतें दर्ज की जा सकती है व इन शिकायतों पर अनुवर्ती कार्यवाही व समाधान हेतु सप्ताह में एक दिन एक निगम अधिकारी की ड्युटी सुनिश्चित की गई है।

- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तगत शहर के चहुँमुखी, बहुआयामी एवं सुनियोजित विकास के लिए तैयार किए गए तथा 9 मार्च, 2007 को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित शहरी विकास योजना (CDP) का सामयिक संशोधन किया जा रहा है। परामर्शदाता द्वारा सभी स्टेक होल्डर विभागों/संस्थाओं/संस्थानों से गहन विचार-विमर्श के पश्चात, आधुनिकतम तकनीकों के सहयोग से शहरी विकास योजना (CDP) की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करके नगर निगम शिमला को प्रस्तुत कर दी गई है, जिसके बार में विभिन्न स्टेक होल्डर विभागों/संस्थाओं/संस्थानों से विचार-विमर्श के बाद अन्तिम रूप दिया जाएगा।

5. शहरी गरीब के लिए परियोजनाएं :

- राजीव आवास योजना के अन्तगत भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के सौजन्य से कृष्णानगर पायलट प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत रू. 33 करोड़ 99 लाख 65 हजार की कुल धनराशि में से प्रथम किश्त रू. 10 करोड़ 67 लाख 24 हजार नगर निगम को प्राप्त हुई है। प्रस्तावित 300 आवासीय इकाईयों में से 224 पात्र चिन्हित लाभार्थियों के लिए तथा 76 किराये के लिए है। इसके अतिरिक्त 30 लाख की लागत से पार्क का निर्माण किया जाएगा तथा 1 करोड़ 30 लाख की लागत से बहु-उद्देशीय परिसर का निर्माण किया जाना है। इस परियोजना के अन्तगत 2 करोड़ 45 लाख रू. की सड़क तथा रास्तों पर खर्च की जाएगी। इस परियोजना के अन्तगत बायपास सड़क कृष्णानगर वधशाला से होली-डे होम के नीचे तक सड़क का निर्माण कार्य किया जाना है। इन सभी कार्यों के लिए मार्च, 2015

के अंत तक निविदाएं आमन्त्रित करके निर्माण कार्य तीव्र गति से आरम्भ करने की समयबद्ध कार्य योजना के अनुसार दिसम्बर, 2016 तक 80 प्रतिशत लाभार्थियों को आवास सुविधा पदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त कृष्णानगर में सीवरेज व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, ड्रेनेज सिस्टम, नालों, रास्तों, सड़क, डंगों इत्यादि का संधार करके फायर फाईटिंग सिस्टम एव ठोस कचरा प्रबन्धन को भी सुदृढ़ किया जाएगा। सामुदायिक उत्प्रेरण सहभागिता तथा स्वयं सहायता समूहों की सक्रियता से जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लक्षित प्रयास किया जाएगा।

- कृष्णानगर के पश्चात् द्वितीय चरण में रूल्दूभटठा वार्ड की चार बस्तियों-ईदगाह कलोनी, कोटहिल क्षेत्र, 12- घर की लाईन तथा 5- घर की लाईन को राजीव आवास योजना के अन्तगत लाभान्वित करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के लिए कार्य प्रगति पर है। सामुदायिक सहभागिता से पात्र लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है तथा हि.प्र. वक्फ बोर्ड से भूमि सम्बन्धित मामलों को उठाया गया है। परामर्शदाताओं का चयन अन्तिम चरण में है। आगामी वित्त वर्ष में इस वार्ड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को भारत सरकार के अनुमोदन के उपरान्त कार्यान्वित करने का लक्ष्य है।
- शिमला शहर के चिह्नित 87 स्लम क्षेत्रों को राजीव आवास योजना के अन्तगत परामर्शदाता (Consultant) द्वारा स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन (SFCPOA) तैयार कर ली गई है जिस पर राशि 35 लाख का खर्च होने की सम्भावना है। स्लम क्षेत्रों के सार्वभौमिक उत्थान के लिए जी.आई.एस. मपिंग (GIS Mapping) सहित वृहद् कार्य योजना का वर्ष 2015-16 में वित्त पोषण प्रस्तावित है।
- 14 करोड़ 1 लाख रुपये की लागत से 384 घरेलू इकाइयों का निर्माण हिमुडा द्वारा आशियाना-II परियोजना के अन्तगत किया जाना था, इसमें से हिमुडा द्वारा 176 घरेलू इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इन 176 इकाइयों में से अभी तक नगर निगम शिमला को 40 आवास हस्तान्तरित कर दिए गए हैं, कुल 176 आवासों में से 94 आवास 31 मार्च, 2015 तक नगर निगम शिमला को हस्तान्तरित कर दिए जाएंगे, जिन्हें पात्र लोगों को आबंटित करने की प्रक्रिया जारी है। शेष 82 आवास जोकि फोरलेन में आ रहे हैं, उनके बारे में सम्बन्धित राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के साथ मामला उठाया गया है। इन 176 आवासों की कुल निर्माण लागत 10 करोड़ होने का सम्भावना है।

6. जल विभाग :

- शिमला शहर में 130 सार्वजनिक शौचालय हैं, जिनमें से 110 का रख-रखाव सुलभ इण्टरनेशनल संस्था द्वारा किया जा रहा है। जी.आई.जैड. के सहयोग से 26 शौचालयों के नवनिर्माण/जीर्णोद्धार की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की गई है। वर्ष 2015-16 में शौचालयों के रख-रखाव हेतु क्लस्टर बेसिज पर निविदाएं आमन्त्रित की जा रही हैं। सामुहिक सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) से इनके संचालन हेतु धन के प्रावधान की प्रस्तावना है।
- चालू वित्त वर्ष में 5 नए सार्वजनिक शौचालयों का पुनर्निर्माण किया गया है, जिसमें से घोड़ा सराय के समीप एक महिला एवं एक पुरुष, रिज, नजदीक मोती मस्जिद तथा नजदीक लिफ्ट पार्किंग का कार्य पूरा हो चुका है तथा ताराहाल स्कूल के नजदीक शौचालय का कार्य लगभग पूर्ण होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त बंगाला कालौनी संजौली, जाखू मंदिर, गौसाई का अहत्था जाखू, अनाडेल, कैथू बाजार, बंगाला कालौनी टूटू, घोड़ा चौकी में दो तथा ऑकलैण्ड टनल के पास नये सार्वजनिक शौचालय बनाये जाने प्रस्तावित हैं।
- नगर निगम शिमला में रिज मैदान पर लगभग रू. 18 लाख की लागत से महिला, पुरुष एवं बच्चों के लिए तीन ई.-शौचालयों का निर्माण वर्ष 2015-16 में किया जाना प्रस्तावित है।
- चालू वित्त वर्ष में पानी के बिलों से 31.12.2014 तक रू. 9 करोड़ 97 लाख की प्राप्ति हुई जोकि इस वित्तीय वर्ष में बढ़कर लगभग रू. 13 करोड़ तक प्राप्त होने का लक्ष्य है तथा आगामी वित्त वर्ष में इसका युक्तिकरण करके यह राशि बढ़कर 18 करोड़ तक होने का अनुमान है।
- चालू वित्त वर्ष में नगर निगम शिमला में सम्मिलित नए क्षेत्रों में 746 नए पानी के कुनैक्शन तथा 248 सीवरेज के कुनैक्शन लगाए गए हैं, जिससे शहर में 28140 पानी के तथा 11069 सीवरेज कुनैक्शन हो गए हैं।
- इस चालू वित्त वर्ष में पानी की लाईनों को बिछाने तथा सुधार हेतु रू. 157.37 लाख तथा सीवरेज व्यवस्था के लिए रू. 225.59 लाख व्यय किए गए। शौचालय निर्माण पर रू. 25.56 लाख व्यय किए गए हैं।

- नगर निगम द्वारा संजौली, ढली व चम्याणा वार्डों के क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के दृष्टिगत राशि 75 लाख की लागत से संजौली में ढिंगुधार पम्प हाउस के संवर्धन एवं उठाऊ पेयजल योजना का कार्य प्रगति पर है तथा इसका राईजिंग-मेन व पम्पिंग मशीनरी का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। शीघ्र ही बिजली ट्रांसफार्मर लगाने के उपरान्त पेयजल आपूर्ति आरम्भ कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 5 लाख लीटर क्षमता वाले भण्डारण टैंक के निर्माण की निविदाएं आमन्त्रित की जा चुकी है।
- विकासनगर, पट्टी रझाणा, मल्याणा, संकटमोचन, महावीर घाटी, घोड़ा चौकी तथा संदल चक्कर क्षेत्रों में सीवरेज की सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से नई सीवरेज लाईने बिछाई गई है। जिन पर रू. 1,75,93,533/- व्यय किए गए।
- टुटू वार्ड के अन्तगत शिव नगर, विजयनगर इत्यादि क्षेत्रों में चली आ रही पानी की समस्या को लेकर नगर निगम द्वारा इस चालू वित्त वर्ष में जल वितरण प्रणाली में सुधार किया गया है।
- पर्यटकों के आकर्षण हेतु टका बैंच में राशि 10 लाख की लागत से फुव्वारा लगाया गया है तथा रिज पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप लगभग राशि 25 लाख की अनुमानित लागत से 2 नये आधुनिक म्युजीकल फुव्वारों का कार्य प्रगति पर है।
- नगर निगम शिमला की परिधि के भीतर तथा बाहर पेयजल आपूर्ति की घरेलू दरों को युक्तिसंगत बनाये जाने हेतु मामला प्रदेश सरकार को भेजा जा चुका है। निगम में कुल 28140 घरेलू व व्यवसायिक पानी के कुनैक्शन है और व्यवसायिक पानी के कुनैक्शन में मीटर दरों पर व घरेलू पानी के कुनैक्शन के बिल फ्लैट दरों पर 210 रू प्रति माह व 15 प्रतिशत सीवरेज सेस जोड़कर उपभोक्ताओं से लिए जाते है, जिससे नगर निगम शिमला को लगभग 13 करोड़ की वार्षिक आय होती है। जबकि सिंचाई एव जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम को रू. 18.20 प्रति किलो लीटर के हिसाब से बिल आता है और यह बिल प्रतिमाह लगभग 2.5 करोड़ व वार्षिक 30 करोड़ हो जाता है। यहाँ यह भी ध्यान में लाया जाता है कि शिमला शहर में बिजली के 65000 उपभोक्ता है, जिनके बिजली के कुनैक्शन लगे हुए है तथा नगर निगम द्वारा इन सभो को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसलिए नगर निगम शिमला को भी बिजली के कुनैक्शनों की भान्ति सभी उपभोक्ताओं को पानी के

कुनैक्शन दिये जाने पर विचार-विमर्श करना होगा, जिससे समस्त शहरवासियो को पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

- शिमला शहर क विभिन्न वार्डों में कई स्थानों पर सीवरेज लाईनों की क्नेक्टिविटी मिसिंग व गल-सड़ गई है। इसके कायाकल्प के लिए 170.35 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर दी गई है तथा मामला शीघ्र ही आर्थिक मामले विभाग, भारत सरकार को वर्ल्ड बैंक/जेईका/ए.डी.बी. द्वारा धन उपलब्ध करवाने हेतु भेजा जा रहा है।
- शिमला शहर में पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए राशि 335.77 करोड़ की लागत से विस्तृत पेयजल परियोजना (DPR) तैयार की गई है और इस परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक/जेईका/ए.डी.बी. से धन उपलब्ध करवाने हेतु मामला भारत सरकार के आर्थिक मामले विभाग को भेजा जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त शिमला शहर में जल वितरण एवं सीवरेज प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करवाई गई है जिसकी कुल लागत 136.93 करोड़ रुपये है। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार के आर्थिक मामले विभाग को वर्ल्ड बैंक/जेईका/ए.डी.बी. से धन उपलब्ध करवाने हेतु भेजी जा रही है।

7. स्वास्थ्य विभाग :

- नगर निगम द्वारा गठित सैहब सोसाईटी को सशक्त बनाने व सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के उद्देश्य से सभी गारबेज क्लैक्टरों को निर्देश दिए गए है कि वह अपने-अपने वार्डों के पाँच घरो/दुकाना/संस्थाओं के मुखिया या सदस्य से प्रतिदिन निर्धारित फार्म पर हस्ताक्षर लेकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे तथा इस फार्म को अपने सम्बन्धित पर्यवेक्षक को देंगे। इसके अतिरिक्त पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आगामी वित्तीय वर्ष में सभी पर्यवेक्षक कूड़ा एकत्रित करने की एवज में लिए जाने वाले निर्धारित शुल्क की रसीद उपभोक्ताओं को मशीन के माध्यम से उपलब्ध करवायेंगे तथा इसका लेखा-जोखा सम्बन्धित को-ऑर्डिनेटर पर्यवेक्षक के माध्यम से अपने कार्यालय में प्रस्तुत करगे। सैहब सोसाईटी के उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 गारबेज क्लैक्टरों को प्रति माह युरोपियन युनियन से प्रोत्साहित किया जाएगा।

- सैहब सोसाईटी के अर्न्तगत सभी वार्डों में उपलब्ध कूड़ा उठाने वाली सभी 25 पिकअप में 01 से 25 तक नम्बर अंकित कर दिए गए हैं तथा इन 25 पिकअप को क्रमानुसार 1 से 25 वार्डों में लगाया गया है ताकि वार्ड के लोग अपने-अपने क्षेत्रों में आने वाली पिकअप को आसानी से पहचान सकें तथा पिकअप के न आने पर वह आसानी से पिकअप में अंकित नम्बर को बताकर नगर निगम द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम में टोल फ्री नम्बर 1916 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसे कंट्रोल रूम द्वारा उपलब्ध रिकार्ड अनुसार आसानी से उस नम्बर की पिकअप के चालक व सम्बन्धित पर्यवेक्षक को सूचना दी जाएगी व शिकायत का शीघ्र निपटारा करने में सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त नगर निगम के सम्बन्धित सफाई निरीक्षकों को भी सफाई सम्बन्धी समस्या के समाधान हेतु शिकायत की जा सकती है।
- नगर निगम द्वारा ठोस कचरा प्रबन्धन परियोजना के अन्तगत भरियाल में स्थापित संयंत्र का बेहतर प्रबन्धन तथा क्षमता संवर्धन की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा शहर का एकत्रित कूड़ा सूचारू रूप से निरन्तर भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त रु. 10 करोड़ 50 लाख की लागत से सैनीटरी लैण्डफिल साईट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ताकि अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रबन्धन किया जा सके।
- दाड़नी का बगीचा (कृष्णानगर) में रु. 26 करोड़ 42 लाख की लागत से आधुनिक वधशाला का निर्माण किया गया है। नगर निगम शिमला की यह वधशाला देश की एकमात्र पहली आधुनिक वधशाला है जिसे भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा भी सराहा गया है। जिन नगर निगमों ने इस आधुनिक वधशाला को लगाना प्रस्तावित किया है वह नगर निगमों इस वधशाला को देखने आ रहे हैं और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी देश की विभिन्न नगर निगमों को इस आधुनिक वधशाला को देखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नगर निगम शिमला के सम्बन्धित अधिकारियों को भी इस वधशाला के अनुभव की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु आयोजित कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जा रहा है। शिमला नगर निगम द्वारा वर्तमान में इस वधशाला का संचालन पट्टे के आधार पर पाँच वर्षों के लिए मै0 माईक्रो ट्रांसमिशन सिस्टम को दिया गया है तथा पट्टेधारक द्वारा अग्रिम राशि 2.14 करोड़ निगम कोष में जमा करवाई गई है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को मध्यनजर रखते हुए नगर निगम द्वारा सुअरों की वधशाला को अलग भवन में स्थापित करने की परियोजना बनाई गई है। जिसके निर्माण पर अनुमानित राशि 70.00 लाख रुपये खर्च होने की सम्भावना है।

- नगर निगम द्वारा पांजड़ी स्थित अस्पताल में जन्म नियन्त्रण हेतु आवारा कुत्तों की नसबन्दी के कार्यक्रम के अर्न्तगत 1.3.2014 से 31.1.2015 तक 765 आवारा कुत्तों की नसबन्दी व टीकाकरण किया गया ।
- सैहब सोसाईटी के अर्न्तगत कार्यरत सभी कर्मचारियों का जनवरी, 2014 से प्रतिमाह निर्धारित वेतन से 12 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि काटना आरम्भ किया गया है जिससे सैहब सोसाईटी के सभी कर्मचारी लाभान्वित होंगे ।

8. वास्तुक विभाग :

- इस चालू वित्त वर्ष में वास्तुक योजनाकार शाखा में भवन निर्माण हेतु 511 प्रस्तावित/संशोधित नक्शों के मामले स्वीकृति के लिए प्राप्त हुए, जिनमें से 502 भवनों के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की गई तथा विभिन्न प्रकार के शुल्को/पैनल्टी/अनापत्ति प्रमाण पत्रों से लगभग रू. 2 करोड़ 86 लाख की प्राप्ति हुई है । पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इस विभाग की कार्य प्रणाली को ऑन लाईन किया जा रहा है जिससे आवेदकों को अपनी नस्ति के सम्बन्ध में जानकारी मिलती रहेगी ।

9. सम्पदा विभाग :

- नगर निगम द्वारा आयुक्त की अध्यक्षता में Town Vending Committees का गठन किया जा चुका है तथा इसकी 2 बैठकें आयोजित की गई है जिसमें National Street Vendors Policy, 2009 तथा Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012 के प्रावधानों के अनुसार शहर में Vending Zones, No Vending Zones तथा Restricted Vending Zones को चिन्हित किया जा रहा है । जिससे लघु व्यवसायियों के पुनर्वास के साथ-साथ जनसुविधा को भी पूर्ण अधिमान दिया जाएगा ।
- नगर निगम शिमला की परिधि में ब्रिटिशकाल के पुराने 5 लेबर होस्टल ह । इसके अतिरिक्त शहर के बढ़ते विकास स्तर के कारण श्रमिकों का आगमन दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उस अनुपात में इन श्रमिकों के ठहरने की कम व्यवस्था है । हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग के सौजन्य से

कोटहिल में एक नए लेबर होस्टल का निर्माण करने की आपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त दो अन्य लेबर होस्टल के निर्माण के लिए स्थान चयनित किये जा रहे हैं। जिसके लिए राशि 4 करोड़ 50 लाख रुपये की अनुदान राशि हेतु सरकार से आग्रह किया गया है।

- वर्ष 2014-15 में नगर निगम को विज्ञापन/होर्डिंग्स स्थलों से माह जनवरी, 2015 तक लगभग ₹. 55 लाख की प्राप्ति हुई है। आगामी वित्त वर्ष के लिए विज्ञापन होर्डिंग की नीति निर्धारण बारे विभागीय कार्यवाही चल रही है और जिससे निगम को 80 लाख की आय अनुमानित है।
- विभिन्न फिल्मों की शूटिंग से चालू वित्त वर्ष में ₹. 25 लाख की आय प्राप्त हुई है। आगामी वित्त वर्ष में फिल्म शूटिंग से लगभग 30 लाख ₹0 की आय सृजित करने की प्रस्तावना है।
- वर्ष 2014-15 में निगम की दुकानों की सबलैटिंग के नियमितकरण प्रभार व किराये में वृद्धि करके लगभग ₹0 65 लाख की एक मुश्त आय प्राप्त हुई है।
- नगर निगम के भराड़ी स्थित विश्राम गृह का कार्य पूर्ण कर दिया गया है जिस पर लगभग 60 लाख का व्यय हुआ है। आगामी वित्त वर्ष में भराड़ी रैस्ट हाउस के आबंटन से लगभग 25 लाख व रिज पर स्थित एल.ई.डी. स्क्रीन के आबंटन से लगभग 12 लाख रुपये की आय प्राप्त होने की सम्भावना है।
- शिमला शहर में भार उठाने वाले श्रमिकों की सुविधा के लिए 50 नये थड़ों (Back Rest) का निर्माण व पुराने थड़ों की मरम्मत करवाई जाएगी।

10. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन :

- स्वर्ण ज्यन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत इस चालू वर्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 8,10,500/- रुपये खर्च हुए हैं जिसमें 73 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया और ऋण अनुदान कार्यक्रम के अन्तर्गत 7,50,000/- रुपये खर्च किए गए हैं। वर्ष 1998 से कार्यान्वित स्वर्ण ज्यन्ती शहरी रोजगार योजना को बदल कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नाम से इस योजना का प्रादुर्भाव हो गया और इस मिशन के तहत आगामी वर्ष में शहरी गरीब लाभार्थियों व 2 लाख तक की आय की सीमा के पात्र युवाओं को भी कौशल विकास कार्यक्रम के तहत रोजगार/स्वरोजगार के लिए सौन्दर्य एवं

सुसज्जित प्रशिक्षण, वेशभूषा एवं परिधान प्रशिक्षण, निर्माण कार्य एवं फ्लम्बर का प्रशिक्षण, रिटेल प्रशिक्षण, टैलीकॉम प्रशिक्षण तथा पर्यटन एवं आतिथ्य का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त लगभग 75 स्वयं सहायता समूहों को गठित करने के उपरान्त बैंक से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में सभी स्वयं सहायता समूह को स्वावलम्बी बनाने के लिए 6 माह के बाद 10 हजार रुपये प्रति समूह दिये जाने का भी प्रावधान है। सभी समूह को उनकी रूचि के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त समूह में कार्य करने हेतु बैंकों के सौजन्य से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आगामी वित्त वर्ष में लगभग 1800 पात्र शहरी गरीबों को इस मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे और लगभग एक करोड़ रुपये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्राप्त होना अनुमानित है।

- शहर में 2 सिटी आजीविका केन्द्र खोलने की भी प्रस्तावना है जिससे शहर में तैयार किए जा रहे कौशल को एक कॉल सेंटर का रूप दिया जाएगा।

11. युवाओं, विद्यार्थियों व महिलाओं के लिए :

- शिमला शहर में युवाओं व विद्यार्थियों के लिए 4 चयनित स्थानों पर खेल मैदान व बैडमिन्टन कोर्ट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा 15 लाख खेल मैदान व 30 लाख बैडमिन्टन कोर्ट के निर्माण हेतु देने प्रस्तावित किए हैं।
- शहरी गरीब महिलाओं के उत्थान हेतु स्वयं सहायता समूह की ओर से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास किया जाएगा ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके।
- शिमला शहर के विभिन्न चयनित स्थानों से आगामी वित्त वर्ष में महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक टैक्सी चलाई जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और शीघ्र ही महिलाओं को इसकी सुविधा मिलेगी।

12. अन्य परियोजनाएं :

- एशियन डेवैल्पमेण्ट बैंक द्वारा वित्त पोषित तथा पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के माध्यम से प्रस्तावित Beautification of Mall Road and

Restoration of Mall Road Project का कार्य रू. 18 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। जिसमें शैलेट डे से लेकर स्कैण्डल प्वाइंट से रिज मैदान तक स्ट्रीट फर्नीचर, फेसाड इम्प्रुवमेण्ट, वर्षा शालिका, प्याऊ, कम्बरमियर ब्रिज, फाउन्टेन, स्ट्रीट एवं फॉकस लाईटिंग, रिटेनिंग वाल का सौन्दर्यकरण वेस्ट-बिन (waste bin) इत्यादि का कार्य, सड़क तथा ड्रेनज की इम्प्रुवमेण्ट के साथ किया जाएगा। रानी झांसी पार्क तथा दौलत सिंह पार्क का भी सौन्दर्यकरण प्रस्तावित है।

- पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के सहयोग से माल रोड़ की तर्ज पर बालूगंज से छोटा शिमला तथा संजौली से रिज, रिज से जाखू इत्यादि सड़कों के सुधार तथा सौन्दर्यकरण की प्रस्तावना है। शहर में लगभग 35 स्थानों पर दिशासूचक तथा ज्ञानवर्धक signages लगाए जाएंगे। तीन प्रमुख स्थानों पर ऐसक्लेटरज लगाने की भी प्रस्तावना है।
- युरोपियन युनियन के सहयोग से 42 माह की समयावधि तथा 1 मिलियन यूरो की लागत वाली परियोजना चलाई जा रही है। अब तक रू. 1 करोड़ 27 लाख की प्राप्ति हुई है। इस परियोजना का 90 प्रतिशत योगदान युरोपियन युनियन द्वारा किया जाएगा तथा 10 प्रतिशत नगर निगम द्वारा वहन किया जाना है। जिसके लिए बजट में प्रावधान किया जाना आवश्यक है। सामुदायिक केन्द्र न्यू शिमला में कार्यालय को आधुनिक उपकरण, फर्नीचर व स्टाफ प्रदान किया है तथा स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में झाँकी, कसुम्पटी में लगभग 800 घरों व संस्थानों का सर्वेक्षण किया गया तथा उनमें से लगभग 200 घरों के लिए Decentralized Waste Water Treatment System (DEWATS) लगाने बारे राजस्व कागजात के अनुरूप साईट चयन कर मामला वन विभाग को एफ.सी.ए. हेतु शीघ्र भेजा जा रहा है। इसी प्रकार एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कसुम्पटी वार्ड में किया जाएगा।
- इस परियोजना के अन्तर्गत नगर निगम शिमला के साथ-साथ मण्डी, नाहन, हमीरपुर के शहरी निकायों को Decentralized Basic Needs Services के बारे प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार विभिन्न विभागों के तकनीकी कर्मचारियों को DEWATS Engineering का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त सिटी सनीटेशन प्लान, एडवांस तकनीकी प्रशिक्षण इत्यादि बारे प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जाने प्रस्तावित है।

- पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून, 2014 को शिमला पर्यावरण जागरूकता अभियान (Shimla Environment Education Programme, SEEP) तथा प्रोजेक्ट वेव-साईट शुरू की गई। सीप पोग्राम के अन्तर्गत 118 स्कूलों का सर्वे कर, 57 स्कूलों के साथ बैठक आयोजित की गई। विभिन्न स्कूलों के लगभग 5000 से अधिक बच्चों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु जानकारी दी गई। बच्चों के माध्यम से ग्रीन फोस ऑफ शिमला बनाकर सफाई में जागरूकता हेतु भागोदारी सुनिश्चित की जाएगी।
- ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए Decentralized Solid Waste Management (DESWAM) विधि का प्रशिक्षण कर लिया गया है और इसे विभिन्न स्कूलों में छात्रों व छात्राओं के माध्यम से लागू किया जाएगा ताकि कचरे को विकेंद्रीकृत विधि से नष्ट कर जैविक खाद में परिवर्तित किया जाएगा।
- वार्ड स्तरीय नियोजन के लिए टूटू वार्ड के सभी भवनों को चिन्हित कर घर-घर का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सीवरेज सप्टिक टैंकों को खाली करने हेतु एक मशीन खरीदी जानी प्रस्तावित है।
- युरोपियन युनियन के तहत 4 नगर परिषदों नाहन, हमीरपुर, मण्डी तथा धर्मशाला की सिटी सैनीटेशन परियोजना बनाई जानी प्रस्तावित है।
- ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए Decentralized Solid Waste Management (DESWAM) विधि के माध्यम से सब्जी मण्डी के जैविक कचरे को नष्ट करने हेतु एक बायोगस प्लांट लगाया जाएगा।
- ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए Decentralized Solid Waste Management (DESWAM) विधि के माध्यम से शहर में 2-3 स्थानों पर Waste Reduction Centre प्वाईट बनाये जाने प्रस्तावित है ताकि डोर-टू-डोर कुलैक्शन से आए कड़े-कचरे में से सूखा तथा पूनचक्रण होने वाले कचरे को अलग कर सिर्फ गिला कचरा ही ठोस कचरा प्रबन्धन प्लांट पर भेजा जा सके।
- इस चालू वर्ष में युरोपियन युनियन के अन्तर्गत नगर निगम शिमला के एक सफाई निरीक्षक, एक सफाई कर्मचारी तथा एक डोर-टू-डोर गारबेज कुलैक्टर को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 15 अगस्त के अवसर पर 5100-5100 रुपये तथा प्रशंसा पत्र दिए गए।

- माल रोड़ की तर्ज पर लोअर बाजार, मिडल बाजार, सब्जी मण्डी, गंज बाजार एवं राम बाजार की सड़को के सुधार व सौन्दर्यकरण हेतु भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है। जिसे पदेश सरकार से धन उपलब्ध करवाकर कार्यान्वित करने की प्रस्तावना है।

13. ई0 गवर्नेस प्रौजेक्ट :

- आगामी वित्त वर्ष में रू. 11 करोड़ 20 लाख की लागत से स्वीकृत ई0 गवर्नेस परियोजना के अर्न्तगत सौफटवेयर तथा हार्डवेयर उपलब्ध करवा कर सभी 22 मॉड्यूल को प्रारम्भ किया जाएगा। इस कार्य को M/S ABM Knowledgeware Pvt. Ltd. को अवारड किया गया है। इससे जनसाधारण को ऑन लाईन सुविधाएं, वार्ड स्तर पर महत्वपूर्ण जानकारियों एवं आधुनिक सुविधाएं तथा त्वरित व पारदर्शी कार्य प्रणाली का लाभ प्राप्त होगा तथा नगर निगम की कार्यकशलता में भी आशातीत वृद्धि होगी।
- सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से तथा संचार कम्पनियों की सहभागिता से शहर को समार्ट सिटी बनाने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ जारी संयुक्त प्रयासों को गति प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण कार्यालयों/संस्थाओं को कनैक्टिविटी तथा सार्वजनिक स्थलों पर वाई-फाई नेटवर्क उपलब्ध करवाने की दिशा में ठोस पग उठाए जाएंगे।

14. प्राप्त सहायता अनुदान :

इस वित्तीय वर्ष में 31.12.2014 तक प्रदेश सरकार के माध्यम से व अन्य स्तरों से नगर निगम को प्राप्त अनुदान राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

1	जिलाधीश कार्यालय के माध्यम से :-		राशि (रूपये)
	क-	डिसेन्ट्रेलाईजड़ प्लानिंग के अन्तर्गत अनुदान	1.00 लाख
	ख-	शहर में कार्यों हेतू अनुदान	7.44 लाख
2	निदेशक, शहरी विकास विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से :-		
	क-	सडकों के रख-रखाव हेतू	121.68 लाख
	ख-	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अनुदान सहायता	230.43 लाख
	ग-	तृतीय/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अनुदान सहायता/चुंगी समाप्ति	1787.54 लाख
	घ-	O&M of Sewerage Scheme under demand No.28 के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि	116.84 लाख
	ड-	पालिका भवन के लिए सडक पर इन्टरलॉकिंग पेवर बिछाने हेतू प्राप्त धनराशि	5.00 लाख
	च-	अर्बन रिस्क रिडक्शन प्रोग्रम के अन्तर्गत	7.17 लाख
	छ-	अन्य स्कीम	0.67 लाख
3	विधायक निधि से		1.00 लाख
4	सांसद निधि से		5.00 लाख
5	अन्य विभागों के माध्यम से:-		
	क-	निदेशक IDIPT-HP, EE(HIMUDA) , महासचिव, रामनगर कल्याण समिति, ढली EE, HPPWD Rural Divn. Dhami , Distt.Youth Service & Sports Officer, Shimla से प्राप्त राशि	78.93 लाख
	ख-	पर्यटन विभाग से हाई मास्ट लाईट लगाने हेतू प्राप्त अनुदान	1.00 लाख
	ग-	एस0जे0वी0एन0एल0 से पार्कों की मुरम्मत हेतू प्राप्त राशि	9.79 लाख
	घ-	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक व अन्य सामाजिक संस्थाओं से बैंच आदि लगाने हेतू प्राप्त राशि	3.29 लाख
6	आधुनिक स्लाटर हाउस के निर्माण हेतू प्राप्त अनुदान :-		300.00 लाख
7	शून्य प्रोजैक्ट और EU Project के अन्तर्गत अनुदान :-		25.20 लाख
8	JNNURM के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान :-		523.30 लाख

कुल प्राप्त अनुदान राशि रूपये -	3225.28 लाख
---------------------------------	-------------

15. विकासात्मक गतिविधियों के लिए बजट अनुमानों का विवरण :

(राशि रूपये लाखों में)

क्रम सं०	विवरण	राजस्व (रख-रखाव)	पुंजीगत (निर्माण)	कुल
1	सड़कों, रेलिंग, डंगों, सीढ़ियों, रास्तों इत्यादि के रख-रखाव व निर्माण के कार्यों हेतु	729.28	141.05	870.33
2	स्ट्रीट लाईट लगाने व उनके रख-रखाव हेतु	100.84	87.49	188.33
3	निगम के भवनों, आवासों के रख-रखाव / निर्माण हेतु	95.22	343.58	438.80
4	पार्किंग का रख-रखाव व निर्माण हेतु	5.00	6.41	11.41
5	नालो की चैनेलाईजेशन/ मुरम्मत/ निर्माण हेतु	26.30	53.65	79.95
6	पानी की लाईनों का रख-रखाव व अतिरिक्त लाईनें बिछाने हेतु	56.72	449.68	506.40
7	सिवरेज लाईनों के रख-रखाव अतिरिक्त लाईनें बिछाने हेतु	41.57	664.61	706.18
8	शौचालय के रख-रखाव/निर्माण हेतु	70.50	121.51	192.01
9	पार्क/प्लेग्राउण्ड इत्यादि विकसित करने हेतु	13.00	49.06	62.06
10	लेबर होस्टल का निर्माण	-	10.00	10.00
11	शहर में नये डम्पिंग स्थान विकसित करने हेतु	-	88.73	88.73
12	सौलिड बेस्ट मैनेजमेंट	207.50	-	207.50
कुल योग :-		1345.93	2015.77	3361.70

16. नगर निगम शिमला के वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान :

नगर निगम शिमला के वर्ष 2014-15 के संशोधित एवं आगामी वित्त वर्ष 2015-16 के बजट अनुमानों का मुख्य शीर्ष-बार विवरण निम्नानुसार है :-

<i>(Rs. in lakhs)</i>					
Major Account Head Code	Actual for the previous year 2013-14	Budget Estimates for the year 2014-15	Actual of First Nine Month for current year 2014-15	Revised Estimates for the current year 2014-15	Budget Estimates for the next year 2015-16
1	2	3	4	5	6
1. राजस्व आय					
110- Tax Revenue	772.75	1502.88	605.39	766.91	1812.59
मुख्य शीर्ष 110-सम्पत्ति कर के अन्तर्गत यूनिट एरिया मैथड पर आगामी वित्त वर्ष में चालू वित्त वर्ष की मांग सहित सम्पत्ति करों से 1812.59 लाख रुपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
120- Assigned Revenues and Compensation	1712.72	1985.10	1930.96	2058.54	2176.29
मुख्य शीर्ष 120- Assigned Revenues & Compensation के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 1966.29 लाख, बिजली की खपत पर फीस से 150.00 लाख व शराब की बिक्री पर फीस से 60.00 लाख रुपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
130- Rental Income- Municipal Properties	480.71	320.00	167.70	280.20	509.50
मुख्य शीर्ष 130- निगम की दुकानों/स्टालों आदि से किराए के रूप में आगामी वित्त वर्ष में 509.50 लाख रुपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
140- Fees & User Charges	2305.67	2875.47	1730.44	2415.72	3725.94
मुख्य शीर्ष 140- फीस एण्ड यूजर चार्जिज के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में पानी के घरेलू/व्यवसायिक कुनैक्शनों के युक्तिकरण करने पर Water Charges से 1800.00 लाख, सीवरेज यूजर चार्जिज से 270.00 लाख, Compounding फीस से 175.00 लाख, ग्रीन फीस से 800.00 लाख, केवल ऑपरेटरज से प्रति केवल कनैक्शन चार्जिज वसूलने से 75.00 लाख, पार्किंग फीस से 150.00 लाख, विज्ञापन एवं होर्डिंग चार्जिज से 70.00 लाख, डम्पिंग साईट चार्जिज से 25.00 लाख, रोड डैमेज चार्जिज से 50.00 लाख व अन्य फीस एवं यूजर चार्जिज से 310.94 लाख रूपय अर्थात् इस मद में कुल राशि रुपये 3725.94 लाख की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
150- Sale & Hire Charges	16.55	14.00	14.47	15.14	14.75
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में स्टोर में पडे स्कैप, कण्डम टिप्पर, डम्पर कन्टेनर की नीलामी व फार्म आदि की बिक्री स 14.75 लाख रुपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
160- Revenue Grant, Contributions & Subsidies	55.39	67.00	5.63	72.03	75.00
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत मुख्यतः केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से निगम द्वारा केन्द्र सरकार की कालोनियों में नियुक्त सफाई स्टाफ के वेतन की प्रतिपूर्ति आदि के रूप में आगामी वित्त वर्ष में 75.00					

लाख रुपये की प्राप्ति का अनुमान है।

1	2	3	4	5	6
170- Income from Investments	96.49	50.01	51.32	60.03	60.00
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निगम निधि से समय-समय पर बैंकों में निवेशित राशि पर ब्याज से आगामी वित्त वर्ष में 60.00 लाख रुपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
171- Interest Earned	46.53	24.48	19.47	28.13	23.99
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत बकाया करों व किराए की राशि पर और बैंक बचत खातों में जमा राशि आदि पर ब्याज से आगामी वित्त वर्ष 23.99 लाख रुपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
180- Other Income	28.04	13.25	31.16	36.31	27.00
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत रिज, माल रोड़, निगम पार्कों व अन्य स्थानों पर फिल्म शूटिंग आदि की अनुमति प्रदान करने से आगामी वित्त वर्ष में 27.00 लाख रुपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
योग राजस्व आय (1)	5514.85	6852.19	4556.54	5733.01	8425.06
उपरोक्त विवरणानुसार आगामी वित्त वर्ष में राजस्व आय के अन्तर्गत निगम की कुल आय 8425.06 लाख रुपये अनुमानित है।					
2. पूँजीगत आय					
320- Grants, Contributions for Specific purposes	3559.70	4999.44	1437.74	1667.72	3547.24
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य संस्थाओं से मुख्यतः राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत 100.00 लाख, 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत 360.00 लाख, Maintenance of ULB roads के अन्तर्गत 121.68 लाख, MPLAD/MLALAD/ 5% DCP व अन्य संस्थाओं से 60.00 लाख, सीवरेज स्कीम के अन्तर्गत 200.00 लाख, आपदा राहत के अन्तर्गत 100.00 लाख, अन्य स्कीमों के अन्तर्गत 229.00 लाख, राजीव आवास योजना के अन्तर्गत 1800.00 लाख, चैलेंज फण्ड के अन्तर्गत 206.34 लाख और सैनिटेशन सर्विसिज के लिए यूरोपियन यूनियन से 370.22 लाख रुपये की अनुदान सहायता की प्राप्ति का अनुमान है।					
330- Secured Loans	0.00	801.12	0.00	0.00	200.00
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में निगम कर्मचारियों के लिए आवासों के निर्माण हेतु राशि 200.00 लाख रुपये वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने की प्रस्तावना है।					
योग पूँजीगत आय (2)	3559.70	5800.56	1437.74	1667.72	3747.24
उपरोक्त विवरणानुसार आगामी वित्त वर्ष में पूँजीगत आय के अन्तर्गत निगम की अनुदान आदि से आय/प्राप्ति 3747.24 लाख रुपये अनुमानित है।					
कुल आय (1+2)	9074.55	12652.75	5994.28	7400.73	12172.30

1	2	3	4	5	6
3. राजस्व व्यय					
210- Establishment Expenses	3849.16	4546.83	3213.30	4459.46	5149.09
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निगम के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों, पेंशन अंशदान, सी.पी.एस. अंशदान, ई.पी.एफ. अंशदान, सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित अन्य लाभ की अदायगी हेतु आगामी वित्त वर्ष के लिए राशि 5149.09 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के भुगतान हेतु राशि रुपये 715.00 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान Pension Deficit Contribution के रूप में रखा गया है।					
220- Administrative Expenses	230.65	527.83	115.23	191.42	519.07
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष के लिए कार्यालय रख-रखाव, बिजली, टैलीफोन, लेखन-सामग्री, फर्नीचर, कम्प्यूटर, निगम वाहनों का बीमा, हल्के वाहनों के लिए इन्धन, विज्ञापन, कन्सल्टैन्सी चार्जिज आदि के प्रशासनिक व्यय हेतु आगामी वित्त वर्ष के लिए राशि 519.07 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस शीर्ष के अन्तर्गत यूरोपियन यूनियन से स्वीकृत प्रोजैक्ट की गतिविधियों से सम्बन्धित व्यय भी सम्मिलित है।					
230- Operations and Maintenance	1375.91	4198.05	1018.54	1400.19	4731.43
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से पानी की खरीद के बिलों के भुगतान हेतु राशि रुपये 3000.00 लाख के प्रावधान सहित निगम की ढाँचागत परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, आवश्यक नागरिक सुविधाओं व अन्य रख-रखाव के कार्यों हेतु आगामी वित्त वर्ष के लिए 4731.43 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।					
240-Interest and Finance Charges	0.05	0.50	0.02	0.50	0.50
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत Interest & Finance Charges हेतु आगामी वित्त वर्ष के लिए राशि 0.50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।					
250- Program Expenses	3.92	9.00	2.36	6.00	7.00
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत Program Expenses हेतु आगामी वित्त वर्ष के लिए राशि 7.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।					
260- Revenue Grants, Contributions and Subsidies	48.94	50.00	128.47	128.47	303.20
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित अनुदान से शहरी गरीबों के उत्थान हेतु कार्यक्रमों पर 125.00 लाख, स्लाटर हाउस प्रोजैक्ट के लिए निगम द्वारा देय राशि 100.00 लाख और यूरोपियन यूनियन से स्वीकृत प्रोजैक्ट के लिए निगम के अंशदान के रूप में राशि 78.20 लाख अर्थात् कुल 303.20 लाख रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया है।					
280- Prior Period Item	6.65	1.00	1.71	2.00	2.00
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत Prior Period Expenses हेतु आगामी वित्त वर्ष के लिए 2.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।					
योग राजस्व व्यय (3)	5515.28	9333.21	4479.63	6188.04	10712.29

उपरोक्त विवरणानुसार आगामी वित्त वर्ष में राजस्व व्यय के अन्तर्गत निगम का राजस्व व्यय 10712.29 लाख रुपये अनुमानित है।

1	2	3	4	5	6
4. पूँजीगत व्यय					
410- Fixed Assets	657.52	2385.35	765.41	977.01	2052.27
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निगम के भवनों, सड़कों, नाले-नालियों के निर्माण, जल वितरण एवं सीवरेज लाईनें बिछाने, स्ट्रीट लाईट लगवाने, कार्यालय प्रयोग हेतू फर्नीचर-फिक्सचर एवं अन्य सामग्री की खरीद हेतू आगामी वित्त वर्ष के लिए राशि 2052.27 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।					
आगामी वित्त वर्ष के लिए पार्षदों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित आवश्यक नागरिक सुविधाओं से सम्बन्धित रख-रखाव और निर्माण कार्य करवाने के लिए राशि रुपये 30.00 लाख प्रति वार्ड के व्यय का प्रावधान मुख्य शीर्ष 230- Operations and Maintenance और 410- Fixed Assets के अन्तर्गत किया गया है। आगामी वित्त वर्ष में विभाग पार्षदों द्वारा प्रस्तावित आवश्यक नागरिक सुविधाओं से सम्बन्धित रख-रखाव और निर्माण कार्यों हेतू व्यय सम्बन्धित बजट शीर्षों से करना सुनिश्चित करेंगे।					
412- Capital Work in Progress	1427.15	3646.30	568.06	753.92	3547.74
इस मुख्य शीर्ष में JNNURM के अन्तर्गत स्वीकृत स्कीमों के तहत प्रगति पर कार्यों के लिए आगामी वित्त वर्ष के लिए राशि 3547.74 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।					
430- Stock in hand (Store Purchase)	241.14	300.00	180.80	200.00	300.00
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निर्माण सामग्री आदि की खरीद हेतू भण्डार के लिए आगामी वित्त वर्ष के लिए राशि 300.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।					
योग पूँजीगत व्यय (4)	2325.81	6331.65	1514.27	1930.93	5900.01
उपरोक्त विवरणानुसार आगामी वित्त वर्ष में निगम का पूँजीगत व्यय 5900.01 लाख रुपये अनुमानित है।					
कुल योग (3+4)	7841.09	15664.86	5993.90	8118.97	16612.30
	1233.46	-3012.11	.38	-718.24	-4440.00
अतः आगामी वित्त वर्ष के बजट अनुमानों में प्रस्तावित आय व व्यय से स्पष्ट है कि निगम का आगामी बजट अनुमान 4440.00 लाख रुपये घाटे का है। इसलिए आगामी वित्त वर्ष के बजट अनुमानों में व्यय के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत रखा गया प्रावधान निगम की आय पर निर्भर करेगा।					

माननीय सदस्यगण मैंने अपने बजट भाषण में नगर निगम की उपलब्धियों, विकास कार्यों, समस्याओं व सुझाव इत्यादि का वर्णन करने का प्रयास किया है तथा आगामी वर्ष के लिये बजट में रखी गई प्रस्तावित राशि का भी वर्णन किया है इन सब बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करना आवश्यक है ।


मैं निगम के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मजदूरवर्ग के कार्य व सहयोग के लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वे अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, यथाशक्ति एवं लग्न से अपना-अपना कार्य करते रहेंगे ।

अन्त में, मैं अपने समस्त सहयोगी पाषर्दों का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से निगम में नीति निर्धारण, विकास कार्य करवाने, लोगों की समस्याओं को हल करने इत्यादि में आज तक आपका सहयोग रहा है भविष्य में भी आप का सहयोग मिलता रहेगा। सामूहिक कार्य प्रणाली व परस्पर सहयोग से ही शिमला शहर का बहुमुखी विकास करवाना तथा इसकी गरिमा को बनाये रखना सम्भव है ।

अतः इन शब्दों के साथ मैं मान्य सदन से वर्ष 2015-16 के बजट पर विचार-विमर्श करने हेतु अनुरोध करता हूँ ।

धन्यवाद ।

25 फरवरी, 2015


(संजय चौहान)
महापौर
नगर निगम शिमला

वित्त, संविदा और योजना समिति की बैठक के विचारार्थ ज्ञापन ।

विभाग का नाम - सामान्य विभाग (लेखा शाखा)
विभागाध्यक्ष - सहायक आयुक्त

1. वर्ष 2014-15 के संशोधित एवं वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान ।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 80(1) के अन्तर्गत नगर निगम शिमला के आगामी वित्त वर्ष 2015-16 के लिए आय एवं व्यय के बजट अनुमान तैयार करने के लिए सभी विभागाध्यक्षों से प्राप्त बजट प्रस्तावनाओं एवं चालू वित्त वर्ष के अनुमोदित बजट अनुमानों के प्रथम 9 मास की आय एवं व्यय के ऑकड़ों के आधार पर शेष 3 मास की आय एवं व्यय के ऑकड़ों का आकलन करके वर्ष 2014-15 के बजट अनुमानों को संशोधित किया गया है। वर्ष 2015-16 के बजट अनुमानों को चालू वित्त वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमानों तथा समस्त विभागाध्यक्षों से प्राप्त बजट प्रस्तावनाओं के दृष्टिगत प्रस्तावित किया गया है।

नगर निगम शिमला की आय के स्रोत सीमित हैं और व्यय में बढौतरी के कारण निगम की देनदारियाँ दिन-प्रति-दिन बढती जा रही हैं। आय के स्रोत सीमित होने के कारण नगर निगम सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से पानी की बल्क खरीद के बिलों की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पा रहा है। परिणामस्वरूप 31.3.2016 तक सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की कुल देनदारी लगभग मु. 21711.18 लाख रुपये हो जाएगी।

समस्त विभागों/अनुभागों से प्राप्त बजट प्रस्तावनाओं एवं माननीय महापौर महोदय द्वारा दिनांक 13.2.2014 को बजट प्रस्तावनाओं पर चर्चा हेतु आयोजित बैठकों में लिए गए निर्णय अनुसार आगामी वित्त वर्ष में शहर में प्रदेश से बाहर रजिस्टर्ड वाहनों के प्रवेश पर ग्रीन फीस लगाने से राशि 800.00 लाख, केवल ऑपरेटरज से प्रति केवल कनेक्शन चार्जिज वसूलने से राशि रुपये 75.00 लाख और पानी के घरेलू/व्यवसायिक दरों के युक्तिकरण से राशि रुपये 600.00 लाख अतिरिक्त आय प्रस्तावित की गई है जिसके अनुसार आगामी वित्त वर्ष 2015-16 में निगम के सभी स्रोतों से आय 11832.30 लाख रुपये व व्यय 16402.30 लाख रुपये प्रस्तावित है।

अतः नगर निगम शिमला के वर्ष 2014-15 के संशोधित एवं वर्ष 2015-16 के प्रस्तावित बजट अनुमानों का समेकित विवरण बजट प्रपत्र “BUD-2, 3 व 4” वित्त, संविदा और योजना समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

हस्ता/-
आयुक्त

हस्ता/-
सहायक आयुक्त

हस्ता/-
लेखा अधिकाकरी

नगर निगम शिमला के चालू वित्त वर्ष 2014-15 के संशोधित एवं आगामी वित्त वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमानों पर समिति द्वारा गहनता से विचार-विमर्श किया गया। समिति द्वारा बजट अनुमानों पर निम्न सिफारिशों की गई:-

1. 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप चालू वित्त वर्ष में प्राप्त होने वाली अनुदान राशि की दूसरी किश्त राशि रूपये 128.13 लाख और तदानुसार आगामी वित्त वर्ष के लिए अनुदान राशि रूपये 360.00 लाख प्रस्तावित की जाए।
2. आगामी वित्त वर्ष में शहर में Playground विकसित करने हेतु राज्य सरकार से राशि 10.00 लाख रूपये की अतिरिक्त अनुदान राशि प्रस्तावित की जाए और तदानुसार इतनी ही राशि का प्रावधान व्यय के मद में भी किया जाए।
3. निगम कर्मचारियों के लिए नए आवासों के निर्माण हेतु धनराशि जुटाने के लिए आगामी वित्त वर्ष में वित्तीय संस्थानों से राशि रूपये 200.00 लाख का ऋण लेने की प्रस्तावना की जाए और तदानुसार इतनी ही राशि का प्रावधान व्यय के मद में भी किया जाए।

विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा वर्ष 2014-15 के संशोधित एवं आगामी वित्त वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमानों को उपरोक्त सिफारिशों करने के उपरान्त अनुमोदित किया गया तथा मामला सदन की विशेष बजट बैठक में लाने की संस्तुति की गई।

बजट अनुमानों पर नगर निगम शिमला द्वारा चर्चा ।

वर्ष 2014-15 के संशोधित एवं वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमानों पर चर्चा से पूर्व, मा0 महापौर महोदय ने मा0 उप-महापौर, पार्षदों, निगम आयुक्त, सहायक आयुक्त, सभी विभागाध्यक्षों, कर्मचारियों व समस्त प्रैस बन्धुओं का स्वागत किया। मा0 महापौर ने बजट भाषण में चालू वित्त वर्ष 2014-15 में किये गये कार्यों और आय व व्यय बारे सदन को अवगत करवाया। बजट भाषण में नगर निगम के प्रत्येक विभाग की कार्यप्रणाली तथा आय-व्यय का भी उल्लेख किया गया।

बजट भाषण समाप्त होने के उपरान्त चर्चा में भाग लेते हुए श्री सुरेन्द्र चौहान, मा0 पार्षद ने कहा कि यह पिछले बजट की ही कॉपी है। पिछली आय-व्यय से इसका कोई comparison नहीं किया गया है। जितना बजट में दिखाया गया है उतने आय के साधन नहीं है। सम्पत्ति कर व पानी के बिलों को नहीं ले पा रहे हैं। मेरे वार्ड में पार्किंगों का कोई स्टेटस नहीं है, सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। नगर निगम के पास आय के साधन कम है। केन्द्र सरकार की स्कीमों का हमें व्याख्यान नहीं करना चाहिए। प्रस्ताव वैसे ही पड़े हैं सिलाई सैन्टर तक नहीं खोल पाए। आशियाना-। का सारा पैसा वापिस चला गया। टैक्स, पानी व विज्ञापनों की साईटों से नगर निगम की आय को बढ़ाया जा सकता है। शुरू हुए कार्य रूक रहे ह। वार्ड कार्यालयों के साथ पुस्तकालय होने चाहिए। वार्डों में खाली पड़ी भूमि पर छोटे-छोटे स्टॉल बना कर उन्हें बेरोजगारों को आवंटित करके उन्हें रोजगार दिया जा सकता है और इससे नगर निगम की आय भी बढ़ सकती है। आंकड़ों के हिसाब से बजट पसंद नहीं आया।

श्री सुशान्त कपरेट, मा0 पार्षद ने कहा कि बजट में खामियां हैं। पार्षद नीधि में 30 लाख + 10 लाख एन्टर किया जाए। मा0 उप-महापौर ने कहा कि मा0 पार्षद को यह समझना चाहिए कि वार्ड में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक पैसा खर्च करने का प्रस्ताव है। श्री सुशान्त कपरेट, मा0 पार्षद ने यह भी कहा कि जिन लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है उन्हें नगर निगम द्वारा रोजगार दिलवाना चाहिए। युवाओं को बजट में जो प्रावधान किया गया है वह बहुत कम है। महिलाओं के लिए सिलाई सैन्टर खोलने का प्रावधान बजट में होना चाहिए। बुजुर्गों को सुविधा देने बारे भी प्रावधान होना चाहिए। बजट में पार्षद नीधि को स्पैसेफिक किया जाए।

श्री शशी शेखर, मा0 पार्षद ने इस बजट का स्वागत किया और कहा कि इसके लिए आयुक्त, सहायक आयुक्त व सभी बधाई के पात्र हैं। बजट में कमियां

भी है व अच्छा भी है। शहर में टैक्स प्रणाली लागू होनी चाहिए। टैक्स व पानी के माध्यम से जो राशि प्राप्त होगी उससे शहर की बेहतरी के लिए कार्य होंगे। जो सुझाव मा0 पार्षदों से प्राप्त होंगे उन्हें शामिल किया जाए। पिछले बजट में जो कहा गया था वह आधा भी नहीं हुआ। प्रत्येक वार्ड में पार्क बनने चाहिए जहां सम्भव व आवश्यक हो वहां पर शौचालय, एम्बुलैन्स रोड़ बनने चाहिए व लोगों को पानी की सुविधा दी जानी चाहिए।

श्रीमति भारती सूद, मा0 पार्षद ने भी इस बजट का स्वागत किया और शहर में जगह-जगह मोबाईल टावर लगे हैं उन पर टैक्स लगना चाहिए। राम बाजार व लोअर बाजार में जो छज्जे इत्यादि बढ़ाए गए हैं उनके लिए फाइन लगना चाहिए। स्ट्रीट वैन्डर के लिए भी प्रावधान होना चाहिए।

श्री मनोज कुठियाला, मा0 पार्षद ने बजट को आंकड़ों का मायाजाल बताते हुए कहा कि बजट में कुछ नया नहीं है और यह पिछले बजट की ही कॉपी है। शहर में सड़कों की हालत खस्ता है। सड़कों की हालत को सुधारा जाना चाहिए। पार्षद नीधि का पूरा फण्ड खर्च नहीं हुआ है। सम्पदा शाखा से पैसा क्यों नहीं आ रहा है? इसके लिए जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। सम्पत्ति कर पूरी नगर निगम सीमा में होना चाहिए। पिछले बजट में शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया था और न ही इस बजट में रखा गया है। शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों की सुविधा के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए।

श्रीमति कान्ता सुयाल, मा0 पार्षद ने इस बजट बारे मिलीजुली प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह बजट अच्छा है। इसके लिए सभी अधिकारीगणों का धन्यवाद किया। मा0 पार्षद ने कहा कि बजट में जो पार्किंगों बारे प्रावधान रखा गया है उस पर कार्यवाही भी होनी चाहिए। इससे नगर निगम की आय भी बढ़ेगी।

श्री दीपक रोहाल, मा0 पार्षद ने कहा कि शहर में जितने भी शौचालय हैं उनमें व्हीलचेयर नहीं जा सकती है। इसलिए शहर में इस तरह से भी शौचालय बनने चाहिए जिसमें व्हीलचेयर व बैसाखी वाले लोग आसानी से जा सकें।

मा0 उप-महापौर द्वारा बजट प्रस्ताव का समर्थन किया गया। मा0 महापौर ने कहा कि टैक्स बारे काफी गम्भीर चर्चा हुई है। इसलिए इसमें निर्णय लिया है कि प्राथमिकता के अनुसार टैक्स भी ले लिया जाएगा। यदि वार्ड कमेठियों का गठन हो जाता है तो काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आय-व्यय पर सभी की चिन्ता स्वभाविक है। मा0 पार्षदों द्वारा दिए गए सुझावों को इसमें सम्मिलित कर दिया जायेगा।

मा0 महापौर ने मा0 पार्षदों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मजदूरवर्ग के कार्य व सहयोग के लिए धन्यवाद किया।

बजट अनुमानों पर नगर निगम शिमला की सहमति ।

विचार विमर्श उपरान्त सदन ने सर्व-सम्मति से वित्त संविदा एवं योजना समिति की सिफारिशों और वर्ष 2014-15 के लिए संशोधित एवं आगामी वित्त वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमानों को अपनाने हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:-

श्री नरेन्द्र कुमार, मा0 पार्षद ने प्रस्ताव किया कि Major Head 210-Establishment Expenses के लिए राशि रूपये 5149.09 लाख की ग्रांट स्वीकार की जाये । जिसका समर्थन श्रीमती लक्ष्मी कश्यप, मा0 पार्षद ने किया ।

प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित हुआ ।

श्रीमती कान्ता सुयाल, मा0 पार्षद ने प्रस्ताव किया कि Major Head 220-Administrative Expenses के लिए राशि रूपये 519.07 लाख की ग्रांट स्वीकार की जाये । जिसका समर्थन कु0 दीक्षा ठाकुर, मा0 पार्षद ने किया ।

प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित हुआ ।

श्रीमती लक्ष्मी कश्यप, मा0 पार्षद ने प्रस्ताव किया कि Major Head 230-Operations and Maintenance Expenses के लिए राशि रूपये 4731.43 लाख की ग्रांट स्वीकार की जाये । जिसका समर्थन श्री नरेन्द्र कुमार, मा0 पार्षद ने किया ।

प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित हुआ ।

श्रीमती उषा देवी लखनपाल, मा0 पार्षद ने प्रस्ताव किया कि Major Head 240- Interest & Finance Charges के लिए राशि रूपये 0.50 लाख की ग्रांट स्वीकार की जाये । जिसका समर्थन श्रीमती उमा कौशल, मा0 पार्षद ने किया ।

प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित हुआ ।

श्रीमती उमा काशल, मा0 पार्षद ने प्रस्ताव किया कि Major Head 250- Programme Expenses के लिए राशि रूपये 7.00 लाख की ग्रांट स्वीकार की जाये। जिसका समर्थन श्री कल्याण चन्द, मा0 पार्षद ने किया।

प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित हुआ।

श्रीमती रजनी सिंह, मा0 पार्षद ने प्रस्ताव किया कि Major Head 260- Revenue Grants, Contributions and Subsidies के लिए राशि रूपये 303.20 लाख की ग्रांट स्वीकार की जाये। जिसका समर्थन श्री सरेन्द्र चौहान, मा0 पार्षद ने किया।

प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित हुआ।

श्री दीपक रोहाल, मा0 पार्षद ने प्रस्ताव किया कि Major Head 280- Prior Period Item (Expenses) के लिए राशि रूपये 2.00 लाख की ग्रांट स्वीकार की जाये। जिसका समर्थन श्री इन्द्रजीत सिंह, मा0 पार्षद ने किया।

प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित हुआ।

श्रीमति कुसुम ठाकुर, मा0 पार्षद ने प्रस्ताव किया कि Major Head 410- Fixed Assets के लिए राशि रूपये 2052.27 लाख की ग्रांट स्वीकार की जाये। जिसका समर्थन श्री सुशान्त कपरेट, मा0 पार्षद ने किया।


प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित हुआ।

श्रीमती निर्मला चौहान, मा0 पार्षद ने प्रस्ताव किया कि Major Head 412- Capital Works in Progress के लिए राशि रूपये 3547.74 लाख की ग्रांट स्वीकार की जाये। जिसका समर्थन श्रीमती भारती सूद, मा0 पार्षद ने किया।

प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित हुआ।

श्री सुशान्त कपरेट, मा0 पार्षद ने प्रस्ताव किया कि Major Head 430- Stock in Hand (Store purchases) के लिए राशि रूपये 300.00 लाख की ग्रांट स्वीकार की जाये। जिसका समर्थन श्री दीपक रोहाल, मा0 पार्षद ने किया। प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित हुआ।

श्री टिकेन्द्र पंवर, मा0 उप-महापौर ने प्रस्ताव किया कि वर्ष 2014-15 के संशोधित तथा वर्ष 2015-16 के प्रस्तावित बजट अनुमान स्वीकार किए जायें जिसका समर्थन श्री शशी शेखर, मा0 पार्षद ने किया। प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित हुआ।


आयुक्त,
नगर निगम शिमला।


Assistant Commissioner,
Municipal Corporation
Shimla

<u>SHIMLA MUNICIPAL CORPORATION</u>								
<u>CONSOLIDATED BUDGET ESTIMATES</u>								
<u>Budgeting Year: 2015-16</u>						<u>BUD - 2</u>		
<u>RECEIPT</u>						<u>(` in Lakhs)</u>		
Major Head	Minor Head	Detailed Head	Head of Account	Actual for the previous year 2013-14	Budget Estimates for the current year 2014-15	Actual of First Nine Month for current year 2014-15	Revised Estimates for the current year 2014-15	Budget Estimates for the next year 2015-16
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>(A) REVENUE RECEIPTS</u>								
110- Tax Revenue	01- Property Tax	01- Residential	110-01-01	187.14	574.34	183.48	238.48	724.34
		02- Commercial	110-01-02	480.97	878.37	319.80	394.80	1078.37
		03- Land	110-01-03	50.48	47.29	61.39	71.39	7.00
	02- Water Tax	01- Water Tax	110-02-01	0.23	0.00	0.15	0.17	0.00
	03- Sewerage Tax	01- Sewerage Tax/Fees	110-03-01	50.48	0.00	39.49	59.49	0.00
	14- Show Tax	01- Show Tax/Fees	110-14-01	3.45	2.88	1.08	2.58	2.88
Sub Total (Tax Revenue)				772.75	1502.88	605.39	766.91	1812.59

120- Assigned Revenues & Compensations	10- Taxes and Duties collected by others	03- Tax on consumption of Electricity/Fees	120-10-03	70.69	150.00	82.34	150.00	150.00
		04- Tax on sale of liquor/Fees	120-10-04	28.30	60.00	61.08	121.00	60.00
	20- Compensation in lieu of Taxes/duties	01- Compensation in lieu of abolition of Octroi (Development Grant under SFC)	120-20-01	1613.73	1775.10	1787.54	1787.54	1966.29
Sub Total (Assigned Revenues & Compensations)				1712.72	1985.10	1930.96	2058.54	2176.29
130- Rental Income from Municipal Properties	10- Rent from Civic Amenities	01- Markets	130-10-01	472.73	15.00	161.41	15.00	18.00
		02- Shopping complexes	130-10-02	0.00	250.00		200.00	270.00
	40- Rent from lease of Lands	01- Rent from lease of Lands	130-40-01	0.00	40.00		50.00	50.00
	80- Other rents	01- Lease Rentals of Municipal Assets	130-80-01	0.00	3.00	6.00	137.00	
		05- Marriage/community halls	130-10-05	7.28	10.00	5.16	8.00	8.00
		08- Labour Hostel	130-10-08	0.63	1.00	1.13	1.20	1.50
	30- Rent from Guest Houses	01- Rent from Guest Houses	130-30-01	0.07	1.00	0.00	0.00	25.00
Sub Total (Rental Income from Municipal Properties)				480.71	320.00	167.70	280.20	509.50
140- Fees & User Charges	11- Licensing Fees	01- D & O (PFA Licence)	140-11-01	18.78	0.00	0.51	0.51	0.00
		02- Hawking	140-11-02	8.10	9.00	4.53	6.00	6.00
		03- Shops (NPFA Licence)	140-11-03	17.52	20.00	2.05	2.50	5.00
		05- Staff Quarters	140-11-05	7.38	8.00	5.18	6.90	7.00

		06- Plumbing License	140-11-06	0.62	0.70	0.53	0.53	0.75
		08- Slaughtering	140-11-08	13.87	12.00	2.35	2.41	0.24
		11- Other	140-11-11	0.43	1.00	0.12	0.15	0.15
	13- Fees for Certificate or Extract	01- Copying	140-13-01	0.54	0.50	0.32	0.40	0.50
		02- Birth & Death Certificate	140-13-02	1.94	1.75	1.35	1.80	2.00
		04- Marriage Certificate	140-13-04	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10
	15- Regularization Fees	02- Regularization	140-15-02	8.47	10.00	56.66	75.00	3.00
		04- Conversion fees (land use)	140-15-04	49.60	37.00	101.39	105.00	130.00
	20- Penalties and Fines	03- Surcharge	140-20-03	11.79	11.00	9.16	12.00	11.00
		04- Others	140-20-04	8.93	10.00	2.16	2.50	3.00
	40- Other Fees	01- Advertisement Fees	140-40-01	50.63	100.00	52.18	65.00	70.00
		06- Sewerage Connection Charges	140-40-06	18.09	30.00	17.71	22.71	25.00
		07- Disconnection Charges	140-40-07	1.15	1.50	1.63	1.88	2.00
		12- Fees for Job Porters	140-40-12	0.02	0.02	0.14	0.15	0.15
		13- Compounding Fees	140-40-13	172.37	500.00	117.99	140.00	175.00
		14- N.O.C. Fees	140-40-14	4.60	3.75	4.75	5.50	5.00
		15- Forest Application processing Fees	140-40-15	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		16- Plantation Fees	140-40-16	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		17- Green Fees on Vehicles	140-40-17	0.00	300.00	0.00	0.00	800.00

	50- User Charges	12- Water Charges (Domestic)	140-50-12	1231.08	1300.00	878.52	1378.52	1800.00
		26- Water Charges (Commercial)	140-50-26					
		11- Pay & Use Toilets	140-50-11	2.55	3.00	1.17	2.34	0.00
		14- Water Tanker	140-50-14	4.80	5.00	4.08	4.75	5.00
		15- Metering charges	140-50-15	27.68	25.00	20.04	25.00	25.00
		20- Parking fees	140-50-20	99.81	120.00	73.60	120.00	150.00
		21- Laboratory Charges	140-50-21	7.02	8.00	4.11	4.25	9.00
		22- Telephone Tower Charges	140-50-22	10.02	8.00	12.58	12.58	15.00
		25- Garbage Clearance/ Disposable Charges	140-50-24	0.00	0.00	1.38	1.38	1.00
		25- Medical Waste Disposable Charges	140-50-25	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
		27- Sewerage User Charges	140-50-27	100.00	100.00	61.65	90.00	270.00
		Cable Connection Charges	140-50-28	0.00	5.00	0.00	0.00	75.00
	60- Entry Fees	01- Parks	140-60-01	2.12	2.00	3.88	4.30	4.30
		01- Service Charges	140-70-01	10.98	0.00	0.33	0.40	0.50
		04- Road Damage Recovery charges	140-70-04	274.59	100.00	237.68	240.00	50.00
		05- Stacking	140-70-05	0.12	0.15	0.07	0.08	0.10
		07- Plan Processing Charges	140-70-07	35.19	25.00	28.43	35.00	50.00
		08- Dumping Site Charges	140-70-08	101.72	110.00	22.05	46.00	25.00

	80- Other Charges	01- Other Charges	140-80-01	0.14	1.00	0.07	0.07	0.15
Sub Total (Fees and User Charges)				2305.67	2875.47	1730.44	2415.72	3725.94
150- Sale & Hire Charges	10- Sale of Products	05- Compost	150-10-05	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
		09- Grass	150-10-09	0.39	0.40	0.00	0.00	0.00
	11- Sale of Forms & Publications	01- Tenders	150-11-01	5.63	4.00	4.20	4.60	4.00
		03- Plans	150-11-03	0.49	0.50	0.29	0.35	0.35
		05- Forms & Publications	150-11-05	2.02	2.00	1.05	1.25	2.00
	12- Sale of Stores & Scrap	02- Obsolete assets	150-12-02	2.61	5.00	5.78	5.78	6.00
	30- Sale of Others	01- Old newspaper	150-30-01	0.03	0.05	0.04	0.05	0.05
	40- Hire Charges for Vehicles	02- Others	150-40-02	3.46	0.35	0.24	0.24	0.25
	41- Hire Charges on Equipments	01- Road Rollers	150-41-01	1.82	1.50	2.87	2.87	2.00
02- Tools & equipments		150-41-02	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	
Sub Total (sale and Hire Charges)				16.55	14.00	14.47	15.14	14.75
160- Revenue Grants, Contribution and Subsidies	20- Re-imburement of Expenses	01- Salary of Health Staff from CPWD & other expenses	160-20-01	51.31	67.00	0.60	67.00	70.00
	30- Contribution towards schemes	01- Contribution towards schemes	160-30-01	4.08	0.00	5.03	5.03	5.00
Sub Total (Revenue Grants, Contribution and Subsidies)				55.39	67.00	5.63	72.03	75.00
170- Income from Investments	10- Interest	01- Fixed Deposits	170-10-01	96.49	50.00	51.29	60.00	60.00
	80- Others	01- Others	170-80-01	0.00	0.01	0.03	0.03	0.00
Sub Total (Income from Investments)				96.49	50.01	51.32	60.03	60.00

171- Interest Earned	10- Interest from Bank Account	01- SB Accounts	171-10-01	3.20	3.00	0.10	3.50	3.00
	20- Interest on Loans and Advances to Employees	01- HBA	171-20-01	1.31	0.74	0.73	0.91	0.44
		05- Vehicle	171-20-05	0.59	0.72	0.54	0.72	0.55
	80- Others	01- Interest on debtors and other receivables- General Tax	171-80-01	31.22	10.00	14.61	18.00	10.00
		02- Interest on debtors and other receivables- Rent	171-80-02	10.19	10.00	3.49	5.00	10.00
		03- Others	171-80-03	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
Sub Total (Interest Earned)				46.53	24.48	19.47	28.13	23.99
180- Other Income	10- Deposits Forfeited	01- EMD	180-10-01	1.48	0.75	2.33	2.70	1.00
		02- Security Deposit	180-10-02	0.72	0.50	0.00	0.00	0.00
	20- Insurance Claim Recovery	01- Insurance Claim Recovery	180-20-01	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
	40- Recovery from Employees	01- Recovery from Employees	180-40-01	6.86	1.00	1.70	1.70	1.00
	80- Miscellaneous	01- Miscellaneous	180-80-01	17.76	10.00	26.72	31.00	25.00
280- Prior Period Item	20- Prior period Income	01- Prior period Income	280-20-01	1.22	1.00	0.41	0.41	0.00
Sub Total (Other Income)				28.04	13.25	31.16	36.31	27.00
TOTAL OF REVENUE RECEIPTS:				<u>5514.85</u>	<u>6852.19</u>	<u>4556.54</u>	<u>5733.01</u>	<u>8425.06</u>

(B) CAPITAL RECEIPTS									
320- Grants, Contribution received for specific purposes	10- Central Government	01- EIUS /NSDP Grant	320-10-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		JNNURM	320-10-01						
		Solid Waste Management for Shimla		5.48	0.00	1.56	1.56	0.00	
		Rehabilitation of water supply system under JNNURM GOI Share-1447.20 State Govt-144.72		1.82	0.00	0.49	0.49	0.00	
		Housing Scheme for Urban Poor of Shimla City ASHIANA-I		0.64	400.00	0.33	0.65	0.00	
		Housing Scheme for Urban Poor of Shimla City ASHIANA-II		0.74	400.00	0.25	0.51	0.00	
		Establishment of eGovernance under JNNURM in MC Shimla		3.40	945.00	192.65	192.65	74.00	
		Beautification of Shimla City		19.84	0.00	9.79	19.79	100.00	
		Project implementation Unit(PIU) under JNNURM in MC Shimla		16.12	10.50	0.27	0.47	0.00	
		Sanitary Landfill Sites at Bharial, The. & Distt. Shimla		59.25	886.46	180.15	180.15	0.00	

		Rajiv Awas Yojna (RAY)		1085.00	1000.00	22.60	22.60	1800.00	
		Challenge Fund for rehabilitation of Street Vendors		0.00	0.00	125.00	125.00	206.34	
		Development of Parking Complex near Sr. Sec. School, Circular Road Sanjauli Shimla (PPP) Format		0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	
		Development of Parking Complex at Chhota Shimla under (PPP) Format		0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	
	02-	C/O Slaughter Houser	320-10-02	1205.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
	02-	SJSRY/NULM	320-10-02	5.76	50.00	0.67	1.00	100.00	
	20-	State Government	01- State Government						
		Merged Area Grant	320-20-01	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
		13th Fin. Comm. Grant		476.88	300.00	230.43	358.56	360.00	
		Maintenance of Roads		121.68	121.00	121.68	121.68	121.68	
		Sewerage Scheme		150.00	0.00	116.84	116.84	200.00	
		Rain Damages/Natural calamities		0.00	0.00	0.00	55.00	100.00	
		Others		124.15	100.00	19.44	50.00	60.00	
	30-	Other Government Agencies	01- Other Government Agencies	320-30-01	91.96	50.00	89.82	95.00	50.00

	60- International Organizations	01- Sunnya Project	320-60-01	32.08	40.00	22.39	22.39	0.00
		Strengthening and empowering Urban Local Authorities in the Delivery of Decentralized Sanitation Services (European Union)		131.78	382.14	2.81	2.81	370.22
	80- Others	01- Others	320-80-01	28.12	10.00	0.57	0.57	5.00
Sub Total (Grants, Contribution for specific purposes)				3559.70	4999.44	1437.74	1667.72	3547.24
330- Secured Loans Received	50- Loan from Bank & Financial Institutions	01- Construction of Staff Quarters	330-50-01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		Loan to meet out ULB share towards JNNURM Projects:						
		Solid Waste Management for Shimla		0.00	160.40	0.00	0.00	0.00
		Rehabilitation of water supply system under JNNURM		0.00	241.20	0.00	0.00	0.00
		Rejuvenation of existing Swerage System for Shimla City under JNNURM		0.00	182.46	0.00	0.00	0.00
		Establishment of eGovernance under JNNURM in MC Shimla		0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
		Sanitary Landfill Sites at Bharial, The. & Distt. Shimla		0.00	105.06	0.00	0.00	0.00
Sub Total (Secured Loans)				0.00	801.12	0.00	0.00	200.00
TOTAL CAPITAL RECEIPTS:				<u>3559.70</u>	<u>5800.56</u>	<u>1437.74</u>	<u>1667.72</u>	<u>3747.24</u>

EXPENDITURE								
Major Head	Minor Head	Detailed Head	Head of Account	Actual for the previous year 2013-14	Budget Estimates for the next year 2014-15	Actual of First Nine Month for current year 2014-15	Revised Estimates for the current year 2014-15	Budget Estimates for the next year 2015-16
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(C) REVENUE EXPENDITURE								
210- Establishment Expenses	10- Salaries, Wages and Bonus	01- Salaries & Allowances-Officers	210-10-01	135.23	174.28	110.30	150.00	154.16
		02- Salaries & Allowances-Staff	210-10-02	2838.02	3286.50	2345.67	3286.50	3657.55
		03- Wages	210-10-03	11.83	13.96	7.07	10.00	13.29
		04- Exgratia	210-10-04	5.50	3.00	2.15	3.00	4.00
	20- Benefits & Allowances	02- LTC	210-20-02	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
		03- Medical Reimbursement	210-20-03	36.46	100.00	12.60	50.00	80.00
		06- Uniform to Staff	210-20-06	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		08- Honorarium to Corporators	210-20-08	9.26	11.82	7.64	11.82	14.18
		09- Honorarium to Officers and Staff	210-20-09	0.75	0.30	0.11	0.15	0.30
		10- Training	210-20-10	1.18	8.00	0.00	5.00	8.00

		12- HRD Activities	210-20-12	36.79	143.90	27.22	34.33	73.00
	30- Pension	03- Pension Contribution	210-30-03	129.37	140.90	94.80	140.90	142.63
		04- Pension Fund Deficit Contribution	210-30-04	456.54	439.00	435.99	540.99	715.00
		05- Contribution to Other Funds-CPS	210-30-05	77.71	86.26	65.15	86.26	108.48
	40- Other Terminal & Retirement Benefits	01- Leave Encashment	210-40-01	50.73	74.92	60.86	74.92	106.68
		02- Death cum Retirement Gratuity	210-40-02	53.90	58.70	39.32	58.70	59.00
		03- Contribution towards EPF	210-40-03	4.16	4.29	4.42	5.89	11.82
Sub Total (Establishment Expenses)				3849.16	4546.83	3213.30	4459.46	5149.09
220- Administrative Expenses	10- Rent, Rates and Taxes	01- Rent, Rates and Taxes	220-10-01	0.00				
		02- Land Revenue	220-10-02	0.00	7.00	1.85	1.85	3.00
		03- Others	220-10-03	4.95				
	11- Office Maintenance	01- Electricity	220-11-01	21.58	25.00	13.41	20.00	25.00
		02- Water	220-11-02	1.52	4.00	0.49	2.00	4.00
		04- Internet Expenses	220-11-04	0.01	1.00	0.43	0.45	0.75
		05- Laboratory Expenditure	220-11-05	4.57	3.00	0.00	2.00	3.00
	12- Communication Expenses	01- Telephone	220-12-01	8.07	15.00	5.84	10.00	15.00
		02- Mobile	220-12-02	0.90	1.50	0.13	0.50	1.50

		03- Fax	220-12-03	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50
	20- Books & Periodicals	02- Newspapers	220-20-02	0.47	0.60	0.40	0.60	0.60
		04- Books	220-20-04	0.09	1.00	0.04	0.20	1.00
	21- Printing and Stationery	01- Service postage	220-21-01	0.57	1.00	0.37	1.00	1.00
		02- Printing	220-21-02	6.31	7.00	3.32	5.00	8.00
		03- Stationery	220-21-03	2.86	6.00	1.17	3.00	5.00
		04- Computer Consumables	220-21-04	1.05	2.50	0.33	0.50	1.00
	30- Travelling & Conveyance	02- Travelling	220-30-02	12.96	2.00	1.07	1.50	2.00
		03- Petrol & Diesel	220-30-03	13.21	15.00	6.66	12.00	15.00
	40- Insurance	01- Insurance	220-40-01	9.32	15.00	7.60	12.00	15.00
	51- Legal Expenses	01- Legal Fees	220-51-01	6.45	16.00	4.89	10.00	12.00
		03- Suit Compromises	220-51-03	0.27	2.00	0.10	2.00	3.00
	53- Professional and Other Fees	01- Architect Fees	220-53-01	0.00	10.00	0.07	1.00	1.00
		02- Engineers Fees	220-53-02	6.66	10.00	10.14	12.00	12.00
		03- Technical Fees	220-53-03	0.00	5.00	0.26	0.30	5.00
		04- Consultancy Charges	220-53-04	32.48	35.00	26.61	35.00	35.00
	60- Advertisement & Publicity	01- Hospitality Expenses	220-60-01	5.26	4.00	1.76	2.50	3.00
		02- Advertisement	220-60-02	18.88	20.00	2.09	12.00	20.00

		03- Organization of Festival	220-60-03	0.60	2.00	0.00	1.00	2.00
	61- Membership & Subscription	01- Membership & Subscription	220-61-01	0.29	0.50	0.29	0.29	0.50
	80- Others	01- Expenditure on Urban Forestry	220-80-01	2.11	2.00	2.18	2.18	1.50
		01- Cremation of unclaimed dead bodies	220-80-02	0.30	1.00	0.22	0.50	0.50
		01- Other Office Expenses	220-80-03	30.79	50.00	3.73	7.00	25.00
		Expenses under EU Project		38.12	263.23	19.78	32.55	297.22
Sub Total (Administrative Expenses)				230.65	527.83	115.23	191.42	519.07
230- Operations & Maintenance	10- Power & Fuel	01- Power & Fuel (Diesel & Pump houses elec. bills)	230-10-01	50.44	85.00	44.86	70.00	75.00
	20- Bulk Purchases	01- Electricity (Street Light) previous liabilities	230-20-01	295.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		Regular Bills of Street Lights		193.96	175.00	113.89	173.00	200.00
		02- Purchase of Water (liability of water bills)	230-20-02	80.69	0.00	178.75	178.75	0.00
	Regular Bills of Bulk purchase of water	0.00		2500.00	0.00	0.00	3000.00	
	40- Hire Charges	01- Machinery Rent	230-40-01	0.36	1.00	0.00	1.00	1.00
		02- Others	230-40-02	0.04	2.00	0.00	2.00	1.00

	50- Repairs & Maintenance-Infrastructure Assets	01- Roads & Bridges	230-50-01	248.13	550.00	341.38	400.00	515.94
		03- Water Supply	230-50-03	17.45	30.00	20.13	30.00	56.72
		04- Street Lighting	230-50-04	7.10	75.00	3.89	10.00	100.84
		05- Storm water/Nallahs	230-50-05	46.81	30.00	20.98	25.00	26.30
		06- Drains	230-50-06	18.59	50.00	33.75	50.00	73.95
		08- Sewerage Lines	230-50-08	8.46	30.00	4.06	30.00	41.57
		09- Foothpath	230-50-09	116.06	110.00	51.50	75.00	130.67
		10- Others	230-50-10	13.75	15.00	6.28	10.00	8.72
	51- Repairs & Maintenance-Civic Amenities	01- Parks	230-51-01	9.79	20.00	2.73	10.00	10.10
		04- Play Grounds	230-51-04	0.00	1.00	0.00	0.00	2.90
		06- Parking Lots	230-51-06	6.07	20.00	0.00	0.00	5.00
		09- Commercial Complex	230-51-09	30.36	50.00	19.15	25.00	13.42
		15- Public Toilets	230-51-15	19.84	75.00	1.08	15.00	70.50
	52- Repairs & Maintenance-Buildings	01- Office Buildings	230-52-01	1.26	10.00	0.16	5.00	26.19
		02- Residential Buildings	230-52-02	32.76	60.00	5.43	15.00	55.61
53- Repairs & Maintenance-Vehicles	01- Repairs & Maintenance-Vehicles	230-53-01	34.52	80.00	34.45	60.00	90.00	

	59- Repair & Maintenance- Others	01- Furniture & Fixture	230-59-01	0.15	2.00	0.00	1.00	2.00
		02- Electrical Appliances	230-59-02	0.56	1.00	0.71	1.00	1.00
		03- Office Equipment	230-59-03	0.61	1.00	0.43	0.50	0.75
		04- Other Fixed Assets	230-59-04	8.71	10.00	2.18	4.00	10.00
	80- Other Operating & Maintenance Expenses	01- Testing & Inspection	230-80-01	0.00	2.00	0.00	1.00	1.75
		02- Water Purification	230-80-02	1.29	3.00	0.50	1.50	3.00
		03- Garbage Clearance	230-80-03	103.14	200.00	112.18	180.00	200.00
		Under Zero Waste Project		28.51	0.00	19.35	22.39	0.00
		07- Health Sanitation Work	230-80-07	0.92	10.00	0.72	4.00	7.50
		08- Others (Medical Waste Disposal Plant)	230-80-08	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
Sub Total (Operations & Maintenance)				1375.91	4198.05	1018.54	1400.19	4731.43
240- Interest & Finance Charges	70- Bank Charges	01- Bank Charges	240-70-01	0.05	0.50	0.02	0.50	0.50
Sub Total (Interest & Finance Charges)				0.05	0.50	0.02	0.50	0.50
250- Programme Expenses	20- Own Programme	01- Own Programme	250-20-01	3.78	8.00	2.36	5.00	6.00
	30- Share in Programme of Others	01- Share in Programme of Others	250-30-01	0.14	1.00	0.00	1.00	1.00
Sub Total (Programme Expenses)				3.92	9.00	2.36	6.00	7.00

260-	Revenue Grants, Contribution and Subsidies	30- Subsidies	03- Health & Others	260-30-03	48.94	50.00	21.47	21.47	125.00
			MC share towards C/O Slaughter House		0.00	0.00	107.00	107.00	100.00
			MC share towards EU Project		0.00	0.00	0.00	0.00	78.20
Sub Total (Revenue Grants, Contribution and Subsidies)					48.94	50.00	128.47	128.47	303.20
280-	Prior Period Item (Expenditure)	80- Other Expenses	01- Other Expenses	280-80-01	6.65	1.00	1.71	2.00	2.00
Sub Total Prior Period Item					6.65	1.00	1.71	2.00	2.00
TOTAL REVENUE EXPENDITURES:					<u>5515.28</u>	<u>9333.21</u>	<u>4479.63</u>	<u>6188.04</u>	<u>10712.29</u>
<u>(D) CAPITAL EXPENDITURE</u>									
410-	Fixed Assets	10- Land	04- Parks	410-10-04	22.00	15.00	10.68	20.00	39.06
			Development of Playgrounds		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
			06- Vacant Municipal Land	410-10-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07- Forest Land (Development of Dumping Sites)	410-10-07	28.17	150.00	63.70	75.00	88.73
		20- Buildings	01- Residential	410-20-01	5.08	75.00	0.00	0.00	15.62
			Construction of Houses (Staff Quarters)		0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
			02- Official/Ward Committee Offices	410-20-02	4.17	50.00	4.96	10.00	14.98
			03- Commercial	410-20-03	34.54	100.00	21.30	30.00	112.98

		05- Toilets/New Toilets	410-20-05	0.00	100.00	24.48	30.00	121.51
		07- Parkings	410-20-07	22.78	50.00	69.64	75.00	6.41
		08- Labour Hostels	410-20-08	0.00	150.00	0.00	0.00	10.00
	30- Roads & Bridges	01- Concrete	410-30-01	14.02	40.00	13.19	18.00	23.64
		02- Black Topped	410-30-02	35.50	150.00	12.62	25.00	38.08
		03- Footpath	410-30-03	88.65	65.00	13.57	40.00	73.37
		04- Bridges	410-30-04	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		05- Stairs & Alleys	410-30-05	6.82	15.00	0.00	0.00	5.96
	31- Sewerage & Drainage	01- Open (Drainage)/ Nallahs	410-31-01	15.83	65.00	35.99	45.00	35.84
		02- Underground (Sewerage Lines)	410-31-02	221.56	300.00	221.53	250.00	664.61
		03- Storm Water Drains/Nallahs	410-31-03	9.90	45.00	4.18	15.00	17.81
	32- Water Ways- General	01- Bore wells (Underground water lines)	410-32-01	39.31	125.00	137.24	150.00	365.51
		02- Open wells (Open water lines)	410-32-02	4.44	7.00	0.00	2.00	5.00
		03- Reservoirs	410-32-03	0.00	10.00	17.20	17.20	79.17

	33- Public Lighting	01- Lamp posts	410-33-01	3.34	125.00	35.41	77.00	87.49
	40- Plant & Machinery	01- Project Machinery	410-40-01	0.00	20.00	5.64	10.00	5.00
		02- Pump House Machinery	410-40-02	6.35	50.00	24.70	30.00	10.00
	50- Vehicles	05- Cranes/JCB	410-50-05	34.75	0.00	1.94	2.00	1.00
		06- Trucks	410-50-06	0.00	0.00	29.31	29.31	0.00
	60- Office & Other Equipments	02- Computers	410-60-02	3.85	0.00	1.82	2.00	1.00
		03- Faxes	410-60-03	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
		04- Photocopiers	410-60-04	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		06- Laboratories	410-60-06	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00
		07- Heaters	410-60-07	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
		08- Others	410-60-08	0.00	0.50	0.20	0.50	0.50
	70 Furniture, Fixtures, Fittings and Electrical Appliances	03- Chairs	410-70-03	0.69	1.00	0.07	1.00	1.00
		05- Electrical Fittings	410-70-05	0.00	0.75	0.93	1.00	1.00
		04- Fans	410-70-04	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
		06- Tables	410-70-06	0.21	1.00	0.73	1.00	1.00
		07- Sofa Sets	410-70-07	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		08- Others	410-70-08	0.37	1.00	0.04	1.00	1.00

	80 Other Fixed Assets	01- Dumper Container	410-80-01	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		02- Dust Bin	410-80-02	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
		03- Others	410-80-03	54.41	40.00	14.34	20.00	10.00
		04- Councillors priorities- (Repair & maintenance works and Original Works in Wards)	410-80-04	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
		<p>Works executed under Councillor's Priorities during 2014-15 has been included/ accounted under relevant heads of Accounts.</p> <p>The Budget provision to meet the Councillor's Priorities @ Rs.30.00 lacs per Ward during the next Financial Year 2015-16 has also been kept under various heads such as Water Supply, Sewerage, Public Toilet, Roads & Building, Street lights. However, all concerned Departments will prepare and book works Estimates under the Councillor's Priorities as per the Budget allocations under the above relevant Heads of Account.</p>						
Sub total (Fixed assets)				657.52	2385.35	765.41	977.01	2052.27
412- Capital Work – in – progress	10- Specific Grants	02- Public Works	412-10-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03- Health	412-10-03	1160.69	0.00	538.13	538.13	41.75
		05- Civic Amenities	412-10-05	170.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	30- Specific Schemes	02- Public works	412-30-02	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		JNNURM Solid Waste Management for Shimla as per condition of the Project report (GOI Share 300.00, & MC Share 160.40)		75.55	0.00	22.73	71.00	0.00

		Reshabilitation of water supply system under JNNURM(as per condition of the Project report) (MC Share 723.60 & Grant from GOI Rs.1447.20)		1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		Challenge Fund for rehabilitation of Street Vendors		0.00	0.00	0.00	125.00	206.34
		Housing Scheme for Urban Poor of Shimla City ASHIANA-I (GOI Grant-300.00)		0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
		Housing Scheme for Urban Poor of Shimla City ASHIANA-II (GOI Grant-500.00)		0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
		Establishment of eGovernance under JNNURM in MC Shimla		0.42	945.00	0.00	0.00	266.65
		Project implementation Unit (PIU) under JNNURM, MC Shimla		0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
		Beautification of Shimla City		15.21	0.00	7.20	19.79	100.00
		Sanitary Landfill Sites at Bharial, The. & Distt. Shimla (GOI Grant 325.00)		0.00	886.46	0.00	0.00	0.00

			Rajiv Awas Yojna		0.00	1000.00	0.00	0.00	2933.00
			Development of Parking Complex near Sr. Sec. School, Circular Road Sanjauli Shimla (PPP) Format		0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
			Development of Parking Complex at Chhota Shimla under (PPP) Format		0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
Sub Total (Capital Work – in – progress)					1427.15	3646.30	568.06	753.92	3547.74
430- Stores	10- Stores	03- Purchases	430-10-03		241.14	300.00	180.80	200.00	300.00
Sub Total (Stores)					241.14	300.00	180.80	200.00	300.00
TOTAL CAPITAL EXPENDITURES:					<u>2325.81</u>	<u>6331.65</u>	<u>1514.27</u>	<u>1930.93</u>	<u>5900.01</u>
TOTAL RECEIPTS (E)=(A+B):					9074.55	12652.75	5994.28	7400.73	12172.30
TOTAL EXPENDITURES (F)=(C+D):					<u>7841.09</u>	<u>15664.86</u>	<u>5993.90</u>	<u>8118.97</u>	<u>16612.30</u>
301- Municipal (General) Fund	90- Excess of Income Over Expenditure	01- Excess of Income Over Expenditure	310-90-01		1233.46	-3012.11	0.38	-718.24	-4440.00
The above Budget Estimates for 2015-16 are subject to realization of funds during the Financial Year.									

<u>SHIMLA MUNICIPAL CORPORATION</u>					
SUMMARY OF BUDGET ESTIMATES					
Budgeting Year: 2015-16			BUD-3		
<u>Rs. in Lakhs</u>					
Particulars	Actual for the previous year 2013-14	Budget Estimates for the year 2014-2015	Actual of First Nine Month for current year 2014-15	Revised Estimates for the current year 2014-15	Budget Estimates for the next year 2015-16
1	2	3	4	5	6
Opening Balance	5132.18	6365.64	6365.64	6366.02	5647.78
Add: Revenue Receipts	5514.85	6852.19	4556.54	5733.01	8425.06
Add: Capital Receipts	3559.70	5800.56	1437.74	1667.72	3747.24
Less: Revenue expenditure	5515.28	9333.21	4479.63	6188.04	10712.29
Less: Capital Expenditure	2325.81	6331.65	1514.27	1930.93	5900.01
<u>Closing Balance</u>	<u>6365.64</u>	<u>3353.53</u>	<u>6366.02</u>	<u>5647.78</u>	<u>1207.78</u>

<u>SHIMLA MUNICIPAL CORPORATION</u>							
MAJOR ACCOUNT HEAD WISE BUDGET ESTIMATES							
Budgeting Year: 2015-16							<u>BUD - 4</u>
(Rs. in lakhs)							
Sr. No.	Major Account Head	Code	Actual for the previous year 2013-14	Budget Estimates for the year 2014-15	Actual of First Nine Month for current year 2014-15	Revised Estimates for the current year 2014-15	Budget Estimates for the next year 2015-16
1	2	3	4	5	6	7	8
1	REVENUE RECEIPTS						
	Tax Revenue	110	772.75	1502.88	605.39	766.91	1812.59
	Assigned Revenues and Compensation	120	1712.72	1985.10	1930.96	2058.54	2176.29
	Rental Income - Municipal Properties	130	480.71	320.00	167.70	280.20	509.50
	Fees and User Charges	140	2305.67	2875.47	1730.44	2415.72	3725.94
	Sale and Hire Charges	150	16.55	14.00	14.47	15.14	14.75
	Revenue Grants, Contributions and Subsidies	160	55.39	67.00	5.63	72.03	75.00
	Income from Investments	170	96.49	50.01	51.32	60.03	60.00
	Interest Earned	171	46.53	24.48	19.47	28.13	23.99
	Other Income	180	28.04	13.25	31.16	36.31	27.00
	Total(1)		5514.85	6852.19	4556.54	5733.01	8425.06

2	REVENUE EXPENDITURE						
	Establishment Expenses	210	3849.16	4546.83	3213.30	4459.46	5149.09
	Administrative Expenses	220	230.65	527.83	115.23	191.42	519.07
	Operations and Maintenance	230	1375.91	4198.05	1018.54	1400.19	4731.43
	Interest and Finance Charges	240	0.05	0.50	0.02	0.50	0.50
	Program Expenses	250	3.92	9.00	2.36	6.00	7.00
	Revenue Grants, Contributions and Subsidies	260	48.94	50.00	128.47	128.47	303.20
	Prior Period Item	280	6.65	1.00	1.71	2.00	2.00
	Total(2)		5515.28	9333.21	4479.63	6188.04	10712.29
3	CAPITAL RECEIPTS						
	Grants, Contributions for Specific purposes	320	3559.70	4999.44	1437.74	1667.72	3547.24
	Secured Loans	330	0.00	801.12	0.00	0.00	200.00
	Total(3)		3559.70	5800.56	1437.74	1667.72	3747.24
4	CAPITAL EXPENDITURE						
	Fixed Assets	410	657.52	2385.35	765.41	977.01	2052.27
	Capital Work in Progress	412	1427.15	3646.30	568.06	753.92	3547.74
	Stock in hand	430	241.14	300.00	180.80	200.00	300.00
	Total(4)		2325.81	6331.65	1514.27	1930.93	5900.01
Total Receipt(1+3)			9074.55	12652.75	5994.28	7400.73	12172.30
Total Expenditure(2+4)			7841.09	15664.86	5993.90	8118.97	16612.30

नगर निगम शिमला की विभिन्न मुख्य शीर्षों से वर्ष 2014-15 के लिए संशोधित एवं वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तावित आय का तुलनात्मक विवरण ।

क्र	मुख्य शीर्ष(Major Head)	वर्ष 2014-15 के लिए संशोधित आय (रूपये लाखों में)	वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तावित आय (रूपये लाखों में)
1	2	3	4
1. राजस्व आय			
1	110 – Tax Revenue	766.91	1812.59
2	120 – Assigned Revenue & Compensation	2058.54	2176.29
3	130 – Rental Income- Municipal Properties	280.20	509.50
4	140 – Fees & User Charges	2415.72	3725.94
5	150 – Sale & Hire Charges	15.14	14.75
6	160 – Revenue Grants, Contributions & Subsidies	72.03	75.00
7	170 – Income from Investments	60.03	60.00
8	171 – Interest Earned	28.13	23.99
9	180 – Other Income	36.31	27.00
योग: (1.राजस्व आय)		<u>5733.01</u>	<u>8425.06</u>
2. पूँजीगत आय			
1	320 – Grants Contributions for Specific purposes	1667.72	3547.24
2	330 – Secured Loans	0.00	200.00
योग: (2.पूँजीगत आय)		<u>1667.72</u>	<u>3747.24</u>
योग: कुल आय (1+2)		<u>7400.73</u>	<u>12172.30</u>

वर्ष 2014-15 की संशोधित आय की तुलना में वर्ष 2015-16 की अनुमानित आय के आँकड़ों में भिन्नता का व्याख्यात्मक विवरण ।

मुख्य शीर्ष(Major Head)	भिन्नता की राशि (रु0 लाखों में)	विवरण
1	2	3
राजस्व आय		
110 – Tax Revenue	(+) 1045.68	चालू वित्त वर्ष 2014-15 में यूनिट एरिया प्रणाली पर सम्पत्ति कर लगाने हेतु Bye-Laws finalize कर दिए गए हैं। आगामी वित्त वर्ष 2015-16 में चालू वित्त वर्ष की कर राशि सहित सम्पत्ति करों की वसूली से आय में बृद्धि की सम्भावना है।
120 – Assigned Revenue & Compensation	(+) 117.75	सरकार से चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप Development Grant में 10% की वार्षिक बढौतरी से अनुदान प्राप्ति में बृद्धि सम्भावित है।
130 – Rental Income- Municipal Properties	(+) 229.30	आगामी वित्त वर्ष 2015-16 में निगम की दुकानों/स्टालों के किराए व संजौली और छोटा शिमला में PPP आधार पर निर्माणाधीन पार्किंग का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर इनसे भी नगर निगम को concession fees (Lease Rental) से आय प्राप्त होनी आरम्भ हो जाएगी। इसलिए इस शीर्ष के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में आय में बृद्धि सम्भावित है।
140 – Fees & User Charges	(+) 1310.22	आगामी वित्त वर्ष 2015-16 में पानी के कनेक्शनों की घरेलू/व्यवसायिक दरों के युक्तिकरण करने से, राज्य से बाहर रजिस्टर्ड वाहनों के शिमला शहर में प्रवेश पर ग्रीन फीस की वसूली, केवल ओपरेटरों से प्रति केवल कुनैक्शन चार्जिज वसूल करने से आय में बृद्धि की सम्भावना है।

1	2	3
150 – Sale & Hire Charges	(-) 0.39	टैण्डर फार्म, स्टोर से स्कैप (पुराना सामान) बेचने आदि से आगामी वित्त वर्ष 2015-16 में आय आंशिक कमी होने की सम्भावना है।
160 – Revenue Grants, Contributions & Subsidies	(+) 2.97	इस शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की कालोनियों म नियुक्त सफाई स्टाफ के वेतन की प्रतिपूर्ति के रूप में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से प्राप्त होने वाली राशि में आगामी वित्त वर्ष 2015-16 में बृद्धि सम्भावित है।
170 – Income from Investments	(-) 0.03	निगम निधि से अधिशेष धनराशि के निवेश पर प्राप्त होने वाले ब्याज से आय में कमी सम्भावित है।
171 – Interest Earned	(-) 4.14	सम्पत्ति करों की अधिकतर बकाया राशि की वसूली चालू वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान की जा चुकी है। इसलिए सम्पत्ति करों की बकाया राशि पर ब्याज प्राप्ति से आय में कमी सम्भावित है।
180 – Other Income	(-) 9.31	अन्य(विविध) स्रोतों से आय में कमी सम्भावित है।
पूँजीगत आय		
320 – Grants Contributions for Specific purposes	(+) 1879.52	आगामी वित्त वर्ष में राजीव आवास योजना व चैलेन्ज फण्ड और अन्य विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत कन्द्र/राज्य सरकार तथा अन्य संस्थाओं से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि में बृद्धि सम्भावित है।
330 – Secured Loans	(+) 200.00	इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में नगर निगम कर्मचारियों के लिए आवासों के निर्माण हेतू राशि रूपये 200.00 लाख का ऋण वित्तीय संस्थानों से लेने की प्रस्तावना है।

नगर निगम शिमला के विभिन्न मुख्य शीर्षों में वर्ष 2014-15 के लिए संशोधित एवं वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तावित व्यय का तुलनात्मक विवरण ।

क्र	मुख्य शीर्ष(Major Head)	वर्ष 2014-15 के लिए संशोधित व्यय (रूपये लाखों में)	वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तावित व्यय (रूपये लाखों में)
1	2	3	4
1. राजस्व व्यय			
1	210 – Establishment Expenses	4459.46	5149.09
2	220 – Administrative Expenses	191.42	519.07
3	230 – Operation & Maintenance	1400.19	4731.43
4	240 – Interest & Finance Charges	0.50	0.50
5	250 – Program Expenses	6.00	7.00
6	260 – Revenue Grants, Contributions & Subsidies	128.47	303.20
7	280 – Prior Period Item/Expenses	2.00	2.00
योग: (1.राजस्व व्यय)		<u>6188.04</u>	<u>10712.29</u>
2. पूँजीगत व्यय			
1	410 – Fixed Assets	977.01	2052.27
1	412 – Capital Work-in-Progress	753.92	3547.74
3	430 – Stock in Hand (Store)	200.00	300.00
योग: (2.पूँजीगत व्यय)		<u>1930.93</u>	<u>5900.01</u>
योग: कुल व्यय (1+2)		<u>8118.97</u>	<u>16612.30</u>

वर्ष 2014-15 के संशोधित व्यय की तुलना में वर्ष 2015-16 के अनुमानित व्यय के आँकड़ों में भिन्नता का व्याख्यात्मक विवरण ।

मुख्य शीर्ष(Major Head)	भिन्नता की राशि (रु० लाखों में)	विवरण
1	2	3
राजस्व व्यय		
210 – Establishment Expenses	(+) 689.63	इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निगम के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन हेतु अंशदान, सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित लाभ की अदायगी हेतु चालू वित्त वर्ष 2014-15 में राशि 4459.46 लाख रूपये की तुलना में आगामी वर्ष 2015-16 के लिए राशि 5149.09 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। जिसमें निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन/उपदान आदि के भुगतान हेतु पेंशन फण्ड में हो रहे घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु भी आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। इसलिए आगामी वित्त वर्ष में स्थापना व्यय में बृद्धि सम्भावित है।
220 – Administrative Expenses	(+) 327.65	इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कार्यालय रख-रखाव, बिजली, टैलीफोन, लेखन-सामग्री, फर्नीचर, कम्प्यूटर, कन्सल्टैन्सी चार्जिज आदि के प्रशासनिक व्यय हेतु चालू वित्त वर्ष 2014-15 में राशि 191.42 लाख रूपय की तुलना में आगामी वित्त वर्ष 2015-16 के लिए राशि 519.07 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। इस शीर्ष में यूरोपियन यूनियन से स्वीकृत प्रोजैक्ट (Strengthening & empowering Urban Local Authorities in the Delivery of Decentralized Saitation Services) के अन्तर्गत किए जाने वाले व्यय सम्मिलित करने से प्रशासनिक व्यय में बृद्धि सम्भावित है।

1	2	3
230 – Operation & Maintenance	(+) 3331.24	इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से पानी की बल्क खरीद व राज्य विद्युत परिषद के स्ट्रीट लाईट बिलो के भुगतान सहित, निगम की ढाँचागत परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, आवश्यक नागरिक सुविधाओं व अन्य रख-रखाव के कार्यों हेतू चालू वित्त वर्ष 2014-15 में राशि 1400.19 लाख रुपये की तुलना में आगामी वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 4731.43 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
240 – Interest & Finance Charges	0.00	इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत Interest & Finance Charges हेतू आगामी वित्त वर्ष 2015-16 के लिए राशि 0.50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
250 – Program Expenses	(+) 1.00	इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत Program Expenses हेतू चालू वित्त वर्ष 2014-15 में राशि 6.00 लाख रुपये की तुलना में आगामी वित्त वर्ष 2015-16 के लिए राशि 7.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
260 – Revenue Grants, Contributions & Subsidies	(+) 174.73	इस मुख्य शीर्ष में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अनुदान राशि से शहरी गरीबों के उत्थान के कार्यक्रमों पर व्यय व आधुनिक वधशाला के निर्माण और यूरोपियन यूनियन द्वारा पोषित प्रोजैक्ट हेतू नगर निगम शिमला के अंशदान हेतू किए गए प्रावधान से व्यय में बृद्धि सम्भावित है।
280 – Prior period Expenses	0.00	इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत Prior Period Expenses हेतू आगामी वित्त वर्ष 2015-16 के लिए राशि 2.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

1	2	3
पूँजीगत व्यय		
410 – Fixed Assets	(+) 1075.26	इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निगम के भवनों, सडकों, नाले-नालियों के निर्माण एवं रख-रखाव, जल वितरण एवं सीवरेज लाईनें बिछाने एवं रख-रखाव, स्ट्रीट लाईट लगवाने एवं रख-रखाव, निगम कर्मचारियों के लिए आवासीय कालोनी के निर्माण, कार्यालय प्रयोग हेतू फर्नीचर-फिक्सचर एवं अन्य सामग्री को खरीद हेतू चालू वित्त वर्ष 2014-15 में राशि 977.01 लाख रुपये की तुलना में आगामी वित्त वर्ष 2015-16 के लिए राशि 2052.27 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
412 – Capital Work-in-Progress	(+)2793.82	इस मुख्य शीर्ष में JNNURM के अन्तर्गत स्वीकृत स्कीमों के तहत प्रगति पर कार्यों के लिए चालू वित्त वर्ष 2014-15 में राशि 753.92 लाख रुपये की तुलना में आगामी वित्त वर्ष 2015-16 के लिए राशि 3547.74 लाख रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया है।
430 – Stock in Hand (Store Purchase)	(+) 100.00	इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निर्माण सामग्री आदि की खरीद हेतू भण्डार के लिए चालू वित्त वर्ष 2014-15 में राशि 200.00 लाख रुपये की तुलना में आगामी वित्त वर्ष 2015-16 के लिए राशि 300.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।